राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई,उत्तरप्रदेश,बिहार,राजस्थान,मध्यप्रदेश,उतरांचल,उतराखंड,दिल्ली,हरियाणा में प्रसारीत

क्रांति समय
SURESH MAURYA
(Chief Editor)
M. 98791 41480
Working. off.: STPI-SURAT, GUJARAT-395023
(Software Technology Park of India, Surat.
www.krantisamay.com
www.krantisamay.in
krantisamay@gmail.com

सुरत-गुजरात,संस्करण सोमवार, 28 जून-2021 वर्ष-4, अंक -155 पृष्ठ-08 मूल्य-01रूपये

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

दिल्ली में आज से खुलेंगे होटल और जिम... एमपी में हटा कोरोना कर्फ्यू

नई दिल्ली। कोरोना वायरस की दूसरी लहर भारत में धीरे-धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि रोजाना होनी वाली मौतों की संख्या चिंचताजनक बनी हुई है। इन सब के बीच राज्यों सरकारों ने कोरोना के कारण लागू प्रतिबंधों में ढ़ील देनी शुरू कर दी ही। दिल्ली में सोमवार से होटल, बैंक्वेट हाल आदि को खोलने और शादी समारोह आयोजित करने की छूट दे दी है। राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन में और ढील देने का फैसला किया है, जबकि मध्यप्रदेश सरकार ने रविवार को कोरोना कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया है।

दिल्ली में कल से खुलेंगे होटल और जिम-दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने सोमवार से होटल, बैंक्वेट हाल आदि को खोलने व शादी समारोह आयोजित करने की छूट दे दी है। जिम व योग संस्थान को पचास फीसद क्षमता के साथ शुरू करने की इजाजत दी गई है। डीडीएमए की तरफ से शनिवार को जारी यह आदेश 28 जून सुबह पांच बजे से पांच जुलाई सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। बीते सप्ताह डीडीएमए ने पब्लिक पार्को, उद्यानों और गोल्फ क्लब को 21 जून से खोलेने की अनुमति दी थी, साथ ही रेस्टोरेंट आदि को भी 50 फीसद बैठने की क्षमता के साथ सुबह आठ बजे से रात 10 बजे खुलने की छूट दी गई थी। मौजूदा आदेश के मुताबिक पिछले दो सप्ताह दी गई सभी छूट जारी रहेंगी। राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों में आई गिरावट को देखते हुए लॉकडाउन में और ढील देने का फैसला किया है। इसके तहत सरकारी कार्यालय अब सायं 7 बजे तक खुल सकेंगे। वहीं, जिन व्यापारिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को टीके की कम से एक खुराक लग चुकी है वे 3 घंटे अतिरिक्त यानी सायं 7 बजे तक खुले रह सकेंगे। इसके अलावा लोगों के लिए 28 जून से सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश की अनुमति दी गई है,

मन की बात में बोले पीएम मोदी-

21 जून को हुआ रिकॉर्ड टीकाकरण, वैक्सीन नहीं लेना खतरनाक

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम %मन की बात% के जरिए देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं। कार्यक्रम के 78वां संस्करण में पीएम मोदी ने टोक्यो ओलंपिक्य का जिक्र करते हुए मिल्खा सिंह को याद किया। पीएम ने कहा कि मिल्खा सिंह का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। मन की बात राष्ट्र के लिए प्रधानमंत्री का मासिक रेडियो संबोधन है, जो हर महीने के अंतिम रविवार को प्रसारित होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाता है।

हमारे देश में अब मानसून का सीजन भी आ गया है। बादल जब बरसते हैं तो केवल हमारे लिए ही नहीं बरसते बल्कि बादल आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बरसते हैं। बारिश का पानी जमीन में जाकर इकठ्ठा होता है,जमीन के जलस्तर को भी सुधारता है इसलिए मैं जल सरंक्षण को देश सेवा का एक ही रूप मानता हूं

कभी-ना-कभी ये विश्व के लिए केस स्टडी का विषय बनेगा कि भारत के गांव के लोगों, हमारे वनवासी-आदिवासी भाई-बहनों ने इस कोरोना काल में किस तरह अपने सामर्थ्य और सूझबूझ का परिचय दिया। गांव के लोगों ने क्वारंटीन सेंटर बनाए, स्थानीय जरूरतों को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल बनाई

एक साल पहले सबके समाने सवाल था कि वैक्सीन कब आएगी?

कभी-ना-कभी ये विश्व के लिए केस स्टडी का विषय बनेगा कि भारत के गांव के लोगों, हमारे वनवासी-आदिवासी भाई-बहनों ने इस कोरोना काल में किस तरह अपने सामर्थ्य और सूझबूझ का परिचय दिया।

आज हम एक दिन में लाखों लोगों को मेड इन इंडिया वैक्सीन मुफ्त में लगा रहे हैं। यही तो नए भारत की नई ताकत है

टोक्यो जा रहे हर खिलाड़ी का अपना संघर्ष रहा है, बरसों की मेहनत रही है। वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं जा रहे हैं बल्कि देश के लिए जा रहे हैं। इन खिलाडियों को भारत का गौरव भी बढ़ाना है और लोगों का दिल भी जीतना है- पीएम मोदी

कोरोना के खिलाफ हम देशवासियों की लड़ाई जारी है, 21 जून को वैक्सीन अभियान के अगले चरण की शुरुआत हुई और उसी दिन देश ने 86 लाख से ज़्यादा लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया..वो भी एक दिन में

जब बात टोक्यो ओलंपिक्स की बात हो रही हो, तो मिल्खा सिंह जी जैसे महान एथलीट को कौन भूल सकता है। कुछ दिन पहले ही कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। जब वे अस्पताल में थे, तो मुझे उनसे बात करने का अवसर मिला था। बात करते हुए मैंने उनसे आग्रह किया था कि आपने तो 1964 में टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, इसलिए इस बार जब हमारे खिलाड़ी ओलंपिक के लिए टोक्यो जा रहे हैं तो आपको हमारे एथलीट का मनोबल बढ़ाना है

शनिवार को प्रधानमंत्री ने एक पुराने मन की बात प्रकरण को साझा किया जिसमें नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर नशीली दवाओं के खतरे पर काबू पाने के कई पहलू शामिल थे। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने लिखा, आइए, हम सब मिलकर नशे को लेकर सही जानकारी साझा करने और नशा मुक्त भारत की कल्पना को साकार करने की प्रतिबद्धता को दोहराएं। याद रखिए, नशा ना तो अच्छी चीज है और ना ही स्टाइल की अभिव्यक्ति।

ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट पर कमेटी के दो सदस्यों ने उठाए सवाल

गुलेरिया के बयान के बाद केंद्र पर हमलावर दिखे केजरीवाल

नई दिल्ली। दिल्ली में ऑक्सीजन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ऑडिट कमेटी के उपसमूह की अंतरिम रिपोर्ट पर अब समिति सदस्यों ने ही असहमति जताई है। दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (गृह) बीएस भल्ला व मैक्स हेल्थकेयर के क्लीनिकल डायरेक्टर संदीप बुद्धिराजा ने अन्य सदस्यों को पत्र लिख रिपोर्ट पर सवाल खड़ा किया है। इससे पहले कमेटी के प्रमुख डॉ. रणदीप गुलेरिया ने कहा कि यह रिपोर्ट अंतरिम है, अंतिम नहीं। भल्ला ने ऑक्सीजन की मांग चार गुना ज्यादा दिखाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये आंकड़े तथ्य से परे हैं। रिपोर्ट में जिस ऑक्सीजन डिमांड (1140 मीट्रिक टन) की बात है दिल्ली सरकार ने कभी भी इस तरह की मांग नहीं की है। जिन चार अस्पतालों की मांग पर यह बात कही गई उसके बारे में 13 मई को कमेटी की बैठक में चर्चा भी की गई थी। इसके बाद कुछ डेटा ठीक कर 183 अस्पतालों में ऑक्सीजन मांग 209 मीट्रिक टन बताई गई थी। इधर, गुलेरिया के बयान के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र पर हमलावर दिखे। दिल्ली में कोविड की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट पर उठे विवाद के बीच दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव बी.एस. भल्ला ने कहा है कि ऐसा लगता होता है कि उक्त रिपोर्ट बिना बदलाव और कमेटी की मंजूरी के केंद्र सरकार को भेज दी गई। वहीं, भल्ला के अलावा मैक्स हेल्थकेयर के क्लीनिकल निदेशक संदीप बुद्धिराजा ने भी रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सवाल उठाए हैं। कमेटी के सदस्यों में से एक भल्ला ने शुक्रवार को एक नोट में कहा कि उन्होंने मसौदा अंतरिम रिपोर्ट पर विस्तार से लिखित तौर पर अपनी आपत्तियां और टिप्पणी 31 मई को कमेटी को भेजी थीं और उसे संशोधित करने तथा सदस्यों की मंजूरी लेने का अनुरोध किया था। भल्ला ने कमेटी के सभी सदस्यों को भेजे अपने नोट में कहा, अंतरिम रिपोर्ट को बिना जरूरी बदलाव किए, कमेटी के सदस्यों के साथ दोबारा साझा किए बगैर और बिना उनकी मंजूरी के भारत सरकार को भेज दी गई। कोविड की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में ऑक्सीजन की मांग को कथित तौर पर बढ़ा-चढ़ा कर पेश करने वाली खबर का हवाला देते हुए भल्ला ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे अधूरी जानकारी के आधार पर दृष्टिकोण बनाया जा सकता है।

कोरोना से हुई मौतों के लिए इंश्योरेंस का कोई प्रावधान नहीं, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर चिंता के बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोरोना होने वाली मौतों के लिए इंश्योरेंस का कोई प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर केंद्र सरकार ने जानकारी दी कि देश में ऐसी कोई नीति नहीं है, जिसके तहत कोरोना से हुई मौतों पर नेशनल इंश्योरेंस कवर मुहैया कराया जाता हो। साथ ही केंद्र ने यह भी कहा कि देश में प्राकृतिक आपदाओं के रिस्क इंश्योरेंस कवरेज के लिए इस महामारी को शामिल करने का भी कोई विचार नहीं किया गया है।

केंद्र सरकार ने वकील गौरव बंसल द्वारा दायर उस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी, जिसमें कोरोना से होने वाली प्रत्येक मौत के लिए पड़ित परिवार को 4 लाख मुआवजा देने की मांग गई है। इस पर केंद्र ने दोहराया कि वित्त आयोग ने अक्टूबर 2020 में आर्थिक सहायता देने के लिए महामारी को आपदा के रूप में शामिल करने के खिलाफ सिफारिश की थी। यह हलफनामा केंद्र सरकार के उस हलफनामे के स्पष्टीकरण में प्रस्तुत किया गया, जिसमें केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा था कि कोविड-19 से मरने वालों के परिवारों को ?

4 लाख की अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह राजकोषीय सामर्थ्य से परे है और केंद्र और राज्य सरकारें गंभीर वित्तीय तनाव में हैं। दरअसल, 21 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र से सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने कोविड-19 से मरने वाले लोगों के परिवारों को चार-चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि नहीं देने का फैसला किया था। साथ ही, शीर्ष न्यायालय ने कहा कि लाभार्थियों के मन में किसी भी तरह के मलाल को दूर करने के लिए एकसमान मुआवजा योजना तैयार करने पर विचार किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने न्यायालय में दाखिल किये गये अपने हलफनामे में कहा कि राकोषीय वित्तीय स्थिति तथा केंद्र एवं राज्यों की आर्थिक स्थिति पर भारी दबाव के चलते अनुग्रह राशि का वहन बहुत कठिन है। हालांकि केंद्र ने न्यायालय से यह भी कहा कि ऐसा नहीं है कि सरकार के पास धन नहीं है। केंद्र ने कहा था कि हम स्वास्थ्य सेवा ढांचा बनाने, सभी को भोजन सुनिश्चित करने, पूरी आबादी का टीकाकरण करने और अर्थव्यवस्था को वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज उपलब्ध कराने के लिए रखे गये कोष के बजाय अन्य चीजों के कोष का उपयोग कर रहे हैं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एम आर शाह की अवकाश पीठ ने सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता से कहा था कि आप(केंद्र) सही स्पष्टीकरण दे रहे हैं

मनमानी फीस वसूलने वाले स्वामी शिवानंद मेमोरियल स्कूल पर गिरी गाज

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने पंजाबी बाग स्थित स्वामी शिवानंद मेमोरियल स्कूल के प्रबंधन अपने हाथ में लेने का फैसला किया है। अभिभावकों की ओर से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि स्कूल बच्चों से मनमानी फीस की वसूली कर रहा है। इसके अलावा स्कूल द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम का भी उल्लंघन किया जा रहा था। दिल्ली सरकार ने अभिभावकों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए इस मामले में एक जांच कमेटी का गठन किया था। जांच के दौरान कमेटी ने छात्रों के अभिभावकों द्वारा उठाए गए मुद्दों को सही पाया और स्कूल के कामकाज में अनियमितता पाई। बयान में कहा गया कि जो कमियां और शिकायतें सही पाई गईं, उन्हें देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत स्कूल प्रबंधन को अपने हाथ में लेने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद स्कूल प्रबंधन को अपना बचाव करने का मौका दिया गया, लेकिन स्कूल प्रबंधन अपने कामकाज में विसंगतियों के बारे में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाया। इसके बाद सरकार ने स्कूल के मैनेजमेंट के अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों में नर्सरी से लेकर 12 वीं कक्षाओं को फिर से खोले जाने तक टीचिंग और लर्निंग एक्टिविटीज के बारे में शनिवार को एक सर्कुलर जारी किया। एक अधिकारिक बयान में कहा गया है कि मौजूदा सत्र के लिए एक्शन प्लान को तीन चरणों में बांटा गया है, जिसमें टीचिंग और लर्निंग प्रक्रिया को आसान बनाना भी शामिल है। पहला चरण 28 जून से शुरू होगा।

जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 5 मिनट में दो बड़े धमाके, पूरा इलाका सील

श्रीनगर। जम्मू एयरपोर्ट परिसर के नजदीक एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल इलाके में तेज धमाका हुआ है। स्टेशन के अत्यधिक सुरक्षा वाले तकनीकी क्षेत्र में शनिवार देर रात पांच मिनट के अंतराल में दो बड़े विस्फोट हुए। अधिकारियों ने की मानें तो फिलहाल पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वॉड और फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है। अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट देर रात करीब सवा दो बजे हुए। पहले विस्फोट के कारण हवाईअड्डे के तकनीकी क्षेत्र में एक इमारत की छत ढह गई। इस स्थान की देखरेख का जिम्मा वायु सेना उठाती है और

दूसरा विस्फोट जमीन पर हुआ। इसमें किसी के हताहत होने की तत्काल कोई जानकारी नहीं मिली थी।

रक्षा प्रवक्ता ने कहा, जम्मू में वायु सेना के अड्डे में धमाके की खबर मिली है। इसमें कोई जवान हताहत नहीं हुआ है और न ही कोई साजो सामान क्षतिग्रस्त हुआ है। जांच चल रही है और विस्तृत विवरण की प्रतीक्षा है। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को कुछ ही मिनटों में सील कर दिया। सूत्रों ने बताया कि वायु सेना अड्डे पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और भारतीय वायु सेना के अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। जम्मू हवाई अड्डा एक असैन्य हवाई अड्डा है।

वैक्सीन पर यूटर्न? मई में 216 करोड़ डोज का वादा, पर अब सरकार ने SC को बताया-135 करोड़ ही मिलेंगी

नई दिल्ली। मई महीने में अगस्त से दिसंबर के बीच वैक्सीन की करीब 216 करोड़ डोज की उपलब्धता का दावा करने वाली मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि अब 135 करोड़ टीके ही उपलब्ध होंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दाखिल किया है, उसके हिसाब से पहले के टारगेट के हिसाब से 81 करोड़ वैक्सीन की कमी का अनुमान है। दरअसल, हलफनामा दाखिल कर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी कि अगस्त 2021 से दिसंबर 2021 तक कोविड-19 के कुल 135 करोड़ टीके उपलब्ध होंगे। इसमें कोविशील्ड के 50 करोड़, कोवैक्सीन के 40 करोड़, बायो ई सब यूनिट वैक्सीन के 30 करोड़, जाइडस कैडिला वैक्सीन के 5 करोड़ और स्पुतनिक वी के 10 करोड़ टीके शामिल होंगे। इसे एक तरह से सरकार का यू टर्न माना जा रहा है, क्योंकि मई में केंद्र सरकार ने अगस्त से दिसंबर के दौरान भारत में 216 करोड़ कोरोना टीकों की मैन्युफैक्चरिंग का ऐलान किया था।

31 जुलाई तक उपलब्ध होगी टीके की 51.6 करोड़ खुराक-सरकार ने कोर्ट से कहा कि 31 जुलाई तक कोविड टीके की कुल 51.6 करोड़ खुराक उपलब्ध कराई जाएंगी, जिनमें से 35.6 करोड़ खुराक पहले ही मुहैया करायी जा चुकी हैं। बच्चों के लिए टीका उपलब्ध कराने की स्थिति को लेकर केंद्र ने एक हलफनामे में कहा कि भारत के दवा नियामक ने 12 मई को भारत बायोटेक को उसके टीके कोवैक्सीन का क्लीनिकल ट्रायल दो से 18 साल के प्रतिभागियों पर करने की

अनुमति प्रदान की थी और इस परीक्षण के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है।

पहले किया था 216 करोड़ टीकों का वादा

बता दें कि मई में केंद्र सरकार ने अगस्त से दिसंबर के दौरान भारत में 216 करोड़ कोरोना टीकों की मैन्युफैक्चरिंग का ऐलान किया था। तब नीति आयोग की स्वास्थ्य समिति के सदस्य डॉ. वीके पॉल ने यह जानकारी दी थी। पॉल ने कहा था, %देश में अगस्त से दिसंबर के दौरान कुल 216 करोड़ कोरोना टीके तैयार किए जाएंगे। ये टीके पूरी तरह से भारत और भारतीयों के लिए ही बनेंगे। उन्होंने कहा था कि इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि आने वाले समय में सभी को वैक्सीनेशन के तहत कवर किया जाएगा।

12 से 18 साल के बच्चों के लिए क्लीनिकल ट्रायल पूरा

अदालत को यह भी बताया गया कि डीएनए टीका विकसित कर रहे जायडस कैडिला ने 12 से 18 वर्ष के आयु-समूह पर क्लीनिकल ट्रायल पूरा कर लिया है और इसे वैधानिक मंजूरी मिलने के बाद यह टीका निकट भविष्य में 12 से 18 साल के बच्चों के लिए उपलब्ध हो सकता है। हलफनामे में सरकार ने यह भी कहा कि देश की पात्र आबादी का टीकाकरण करने के वास्ते टीका उपलब्ध रहेगा।

लोगों को व्यवहार पर निर्भर करेंगे मामले

वहीं, केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को यह भी बताया कि वे देश में कोविड-19 के मामलों में इजाफा होने की सूरत में इससे निपटने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और इसके बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत कर रहे हैं। शीर्ष अदालत में दायर हलफनामे में केंद्र ने कहा कि इस चरण में मामलों में फिर से वृद्धि होने की संभावना जताना काल्पनिक होगा। हालांकि, संक्रमण के मामलों में इजाफा वायरस के व्यवहार और लोगों के व्यवहार के पैटर्न पर निर्भर करेगा कि क्या वे कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन कर रहे हैं या नहीं?

इसमें कहा गया कि राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को लगातार सतर्कता बरतने को लेकर आगाह किया गया है और उन्हें संबंधित राज्य में कोविड के प्रसार में बढ़ोतरी होने की दशा में इससे निपटने के लिए सभी तैयारियां करने को भी कहा गया है।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संपादकीय

लोकतंत्र का दीया

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया बहाल करने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से प्रदेश के नेताओं की बैठक का आयोजन और उसमें हुआ विचार-विमर्श लोकतंत्र की ताकत की निशानदेही कराता है। लोकतंत्र का दीया आतंकवाद और पृथकतावाद के तूफान को हरा सकता है यह इस बैठक ने स्पष्ट कर दिया। इस बैठक से यह भी स्पष्ट हुआ कि प्रदेश में बहुत जल्द राजनीतिक प्रक्रिया बहाल की जाएगी। बैठक में प्रधानमंत्री ने नेताओं को यह भरोसा भी दिलाया कि चुनाव के बाद जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दरजा भी दिया जाएगा। 5 अगस्त 2019 को संविधान का अनु. 370 हटाए जाने के बाद केंद्र और राज्य के प्रमुख नेताओं के बीच यह पहली बैठक थी, जिसे सभी नेताओं ने सराहा। बैठक की सबसे बड़ी सफलता इस बात से भी जाहिर होती है कि अनु. 370 का मुद्दा बैठक में बाधक नहीं बना। जम्मू-कश्मीर राज्य का विशेष दरजा समाप्त करने के बाद वहां के कुछ प्रमुख राजनीतिक नेताओं को जेल में ड़ाल दिया गया था और कुछेक को नजरबंद किया गया था। जाहिर है इसके कारण केंद्र और प्रदेश के नेताओं के बीच कटुता बढ़ गई थी। दो वर्ष पहले जब संसद में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पेश किया गया था तब विपक्षी नेताओं ने इसे अंधकार युग की शुरुआत करार दिया था। पीड़ीपी की नेता महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं ने तो ज्वालामुखी फटने की चेतावनी दी थी, जिसकी जद में प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा मुल्क आ सकता है। पिछले दो वर्ष के घटनाक्रम ने इन सब आशंकाओं को निर्मूल साबित कर दिया। मोदी सरकार ने जो राजनीतिक जुआ खेला था उसमें वह सफल रही। इससे भाजपा को राजनीतिक फायदा हुआ यह कम महद्भव का है। वास्तव में इस फैसले से राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूती मिली तथा आतंकवाद और पृथकतावाद की कमर टूट गई। देश में विरोध के सुरों के साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो दुष्प्रचार अभियान चलाया गया उसे प्रदेश और देश के लोगों ने नाकाम कर दिया। हाल ही में केंद्र ने प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए 28 हजार 400 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ वर्ष 2037 तक मंजूरी दी गई है। इसका मुख्य लक्ष्य रोजगार सृजन करना है। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रदेश में शांति और विकास की प्रक्रिया जारी रहेगी।

अमन-विकास की घाटी

यह सुखद ही है कि प्रधानमंत्री और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के नेताओं की सर्वदलीय बैठक गर्मजोशी और भरोसे के बीच संपन्न हुई। राज्य का विशेष दर्जा खत्म किये जाने के करीब दो साल बाद हुई बातचीत इस मायने में भी महत्वपूर्ण रही कि इससे संवादहीनता खत्म हुई है। गुरुवार को दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जम्मू-कश्मीर के चौदह नेताओं ने साढ़े तीन घंटे तक चली बातचीत में भाग लिया, जिसमें प्रदेश के चार पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद व महबूबा मुफ्ती भी शामिल थे। बातचीत की शुरुआत इस बात का संकेत भी है कि अब केंद्र पहले की तरह सख्त नहीं है और विपक्ष भी पहली जैसी तनातनी के मूड में नहीं है। अब तक केंद्र के ऐसे प्रयासों के बाद घाटी में बंद का आह्वान किया जाता था। कहीं न कहीं कश्मीरी नेता यह मान चुके हैं कि राज्य का पूर्व जैसा विशेष दर्जा हासिल कर पाना अब संभव नहीं है। ऐसे में जितना जल्दी हो सके, लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हो, ताकि उनका भी खोया जनाधार लौट सके। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि वहां चुनाव होने चाहिए ताकि लोगों को एक लोकतांत्रिक सरकार मिल सके। जिससे प्रदेश के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। निस्संदेह राजनीतिक नेतृत्व ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। केंद्र सरकार ने कहा भी है कि जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना हमारी वरीयता में शुमार है। जिसके लिये जरूरी है कि परिसीमन तेजी से हो ताकि विधानसभा चुनाव हो सकें और विकास की राह पर बढ़ने के लिये जनता को एक चुनी सरकार मिल सके। उम्मीद है कि केंद्र की पहल पर हुई बातचीत जम्मू-कश्मीर की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेगी। इस बातचीत पर देश ही नहीं, पूरी दुनिया की निगाह रही है। ऐसे में अच्छे वातावरण में हुई बातचीत का क्रम निरंतर जारी रहना चाहिए।

यह सुखद ही है कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाये जाने के बाद जो तल्खी पैदा हुई थी, उस पर अब विराम लगा है। केंद्र के कदम का विरोध कर रहे जिन नेताओं को नजरबंद किया गया था, वे बातचीत की टेबल पर लौटे हैं। जिसे राज्य के राजनीतिक भविष्य की दिशा में सकारात्मक पहल कहा जायेगा। इससे राज्य के विकास का ढांचा तैयार करने में मदद मिलेगी। संवाद व सकारात्मक व्यवहार से ही बात आगे बढ़ पायेगी। बातचीत इस बात का भी पर्याय है कि जम्मू-कश्मीर के नेताओं का केंद्र पर भरोसा कायम हुआ है जो प्रदेश में विकास व लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा। अच्छा है कि जम्मू-कश्मीर के दिग्गज नेता राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। जहां तक जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात है तो केंद्र सरकार पहले ही कह चुकी है कि अनुकूल परिस्थितियां होते ही राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जायेगा। वहीं केंद्र ने यह भी साफ कर दिया है कि पड़ोसी देश से बातचीत के महबूबा मुफ्ती के सुझाव पर वह विचार नहीं करेगी। केंद्र से हुई इस बातचीत में कोई एजेंडा नहीं था लेकिन हर नेता को अपनी बात खुलकर रखने की छूट थी। कुछ नेताओं ने लोगों की जमीन-जायदाद को सुरक्षा देने, स्थानीय लोगों के लिये नौकरी आरक्षित करने, कश्मीरी पंडितों की वापसी सुनिश्चित करने की मांग की। अनुच्छेद 370 का मामला अदालत में विचाराधीन होने के कारण चर्चा में नहीं आया, लेकिन उमर अब्दुल्ला व महबूबा मुफ्ती इसकी बहाली के लिये संघर्ष की बात करते रहे। हालांकि, वे भी जानते हैं कि यह अब संभव नहीं है। वहां अब शेष देश के समान कानून ही मान्य होंगे।

विदेशी मीडिया

दूषित जल की चिंता

अगर परमाणु-दूषित जल को समुद्र में बहाने की योजना है, तो यह दुनिया को विश्वास दिलाना होगा कि यह समुद्री पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। समुद्र में छोड़ने से पहले उस जल से सभी हानिकारक रेडियोधर्मी तत्वों को हर संभव तरीके से समाप्त करना होगा। ऐसा करने के बजाय, ऐसा लगता है कि जापान दुनिया की आंखों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए चीन और कोरिया गणराज्य ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 47वें सत्र में योजना को लेकर चिंता जताई है। केवल इन दोनों देशों के लोग ही इस दूषित जल के खतरे के प्रति सचेत नहीं हैं, केवल यही दोनों देश इस जल को प्रशांत महासागर में डालने के जापान सरकार के फैसले का विरोध नहीं कर रहे हैं, जापान के भीतर भी योजना का बहुत विरोध है। जापानी मीडिया ने हाल ही में बताया कि फुकुशिमा में नष्ट परमाणु ऊर्जा संयंत्र की संचालक टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी दूषित पानी से रेडियोधर्मी ट्रिटियम को साफ करने के लिए प्रौद्योगिकी की मांग कर रही है। इसलिए यह मानने के कारण हैं कि उस दूषित जल में बहुत सारे रेडियोधर्मी तत्व हैं, जो प्रशांत महासागर में छोड़े जाने पर जल को दूषित कर देंगे। समुद्री जीवन व समुद्री भोजन खाने वालों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करेंगे। एक जापानी अधिकारी ने दावा किया है कि पानी पीने के लिए पर्याप्त सुरक्षित है। अगर जल वास्तव में पीने के लिए सुरक्षित है, तो इसे साबित करने के लिए इसमें से कुछ जल का उपयोग उसे करके दिखाना चाहिए। अगर यह सुरक्षित है, तो जापान इतने कीमती संसाधन को समुद्र में बहाकर क्यों बर्बाद करे? यह बताया गया था कि दूषित जल रखने वाले कुछ कंटेनर मई में लीक हुए थे और कुछ दूषित पानी पहले ही समुद्र में लीक हो चुका है। जापान को इस फैसले पर बार-बार सोचने की जरूरत है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भी चर्चा करनी चाहिए कि इस जल का कैसे निपटारा किया जाए। पूरी दुनिया को जापान पर दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि यह मामला सभी देशों की पर्यावरण और पारिस्थितिक सुरक्षा से संबंधित है।

दिल के करीब आई घाटी, नवयुग की नई परिपाटी

उपेन्द्र राय

भारत भूमि पर साक्षात स्वर्ग जम्मू-कश्मीर। इस राज्य को स्वर्ग की उपमा इसलिए दी जाती है, क्योंकि प्रकृति ने इस स्थान को जो कुछ भी दिया, वो सब कुछ भारतभूमि के अभिन्न अंग की मुद्रा के हिस्से हैं।

उदाहरण के लिए केसर की क्यारियों से केसरी मिला, बर्फ से श्वेत और चिनार के हरे रंग को लेकर देश का सम्मान तिरंगा बनाया गया। अब इसी तिरंगे की छांव में अमन की राह पर बढ़े कश्मीर में कुदरत ने अपना सर्वोच्च नियम परिवर्तन लागू कर दिया जिसका पहला दृश्य था कश्मीरियत के नाम पर तल्ख नजरिए से घूरने वाले चेहरों का सौहार्द्र।

जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली और राजनीतिक प्रक्रिया को शुरू करने के इरादे से दिल्ली में बुलाई सर्वदलीय बैठक में माहौल इतना सद्भावपूर्ण रहा कि दुनिया दंग रह गई। लगा ही नहीं कि ये वही नेता थे जिन्हें दो साल पहले अनुच्छेद 370 को प्रभावहीन बनाने से पहले या तो नजरबंद कर लिया गया था या फिर जेलों में डाल दिया गया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि सर्वदलीय बैठक में अनुच्छेद 370 पर चर्चा हुई ही नहीं। सबका जोर इसी बात पर रहा कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दोबारा मिले और वहां चुनाव हो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यह पहल इस मायने में हमेशा सफल मानी जाएगी कि हफ्ते भर में उन्होंने इस सर्वदलीय बैठक को अंजाम दे डाला। इतने समय में तो किसी बड़े राजनीतिक दल की अपनी केन्द्रीय बैठक तक नहीं हो पाती है। निश्चित रूप से अंदरखाने एक सहमति बना ली गई होगी जिस वजह से सर्वदलीय बैठक में कोई बाधा नहीं आई। महबूबा मुफ्ती ने बैठक में शामिल होने को लेकर शुरु आती झिझक दिखलाई थी लेकिन वह भी जल्द दूर हो गई।

> जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र की बाहली और राजनीतिक प्रक्रिया को शुरू करने के इरादे से दिल्ली में बुलाई सर्वदलीय बैठक में माहौल इतना सद्भावपूर्ण रहा कि दुनिया दंग रह गई। लगा ही नहीं कि ये वही नेता थे जिन्हें दो साल पहले अनुच्छेद 370 के प्रभावहीन बनाने से पहले या तो नजरबंद कर लिया गया था या फिर जेलों में डाल दिया गया था। चौंकाने वाली बात रही कि सर्वदलीय बैठक में अनुच्छेद 370 पर चर्चा हुई ही नहीं। सबका जोर इसी बात पर रहा कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दोबारा मिले.

इस बैठक से जुड़ी एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें 14 नेताओं को नाम के साथ निमंत्रण दिया गया था। किसी भी दल को अलग-अलग निमंत्रण नहीं दिया गया था, फिर भी किसी ने आपत्ति नहीं की। अगर आपत्ति होती तो इसे सर्वदलीय बैठक के बजाए 14 नेताओं के साथ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उपराज्यपाल की बैठक कही जाती। मगर, इस किस्म का विवाद भी नहीं उठा।

निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शक्तिशाली छवि सर्वदलीय बैठक में कारगर साबित हुई। उनकी पहल को सबने एक अवसर के तौर पर देखा। उम्मीद बन आई कि जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हो सकती है। सर्वदलीय बैठक में चर्चा के बाद यह उम्मीद और बढ़ी है। जम्मू-कश्मीर में सक्रिय सभी दलों को एक तरह से समेटने का काम हुआ है। सभी एक टेबल पर आए, यह बात महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय नजरिए से भी यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक समस्या को हल करने के लिए सभी पक्ष एक साथ विचार-विमर्श कर सकते हैं क्योंकि यह भारत का आंतरिक मामला है। चूंकि बैठक का एजेंडा तय नहीं था और यह अचानक बुलाई गई थी, इसलिए इस बैठक के मकसद पर बातें भी अलग-अलग तरीकों से हो रही हैं। मगर, विदेशी दबाव में बैठक बुलाने की थ्योरी में बहुत दम नजर नहीं आता। भारत क्वाड से जुड़ कर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ कदमताल कर रहा है। चीन को भारत की यह बात पसंद नहीं आ रही है, लेकिन भारत की सीमा पर लगातार चीन का रवैया भी भारत को नागवार गुजर रहा है। वास्तव में जिस विस्तारवाद की ओर चीन कदम उठा रहा है और आर्थिक क्षेत्र में वह महाशक्ति बनने की आकांक्षा को विस्तार दे रहा है, उसे देखते हुए भारत को अपना व्यापारिक और कूटनीतिक हित सुनिश्चित करना जरूरी हो जाता है।

निश्चित रूप से अमेरिका में बाइडेन प्रशासन आने के बाद से ईरान के प्रति उसका रुख बदला है। इजराइल में भी नेतन्याहू के सत्ता से बाहर हो जाने के बाद फिलीस्तीन को देखने के नजरिए में बदलाव आता दिख रहा है। मगर, जम्मू-कश्मीर के विषय को अमेरिका किसी नए तरीके से देखेगा इसकी गुंजाइश नहीं के बराबर है। उल्टे चीन के विस्तारवाद के कारण भारत के प्रति दुनिया की सहानुभूति बढ़ेगी। हालांकि पाकिस्तान भी फाइनेन्शियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ पाया है फिर भी उसके रिकॉर्ड की तारीफ की गई है। तालिबान के साथ भारत की बातचीत का महत्व अफगानिस्तान में अमेरिकी भूमिका को लेकर अधिक है। इसका भारत प्रशासित क्षेत्र की सियासत से कोई सीधा संबंध नहीं है। जाहिर है कि जम्मू-कश्मीर की बैठक पर विदेशी दबाव या प्रभाव की थ्योरी जुबान पर चढ़ती नहीं दिखती।

जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहले ही पाकिस्तान को अलग-थलग कर चुके हैं। यूरोपीय यूनियन के प्रतिनिधिमंडल को जम्मू-कश्मीर का दौरा कराकर उन्होंने यह दिखाया था कि जम्मू-कश्मीर को लेकर दुनिया में जो आंसू बहाए जा रहे हैं, वे निर्थक हैं। दुनिया का कोई भी देश जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म करने की पहल पर पाकिस्तान के हो-हल्ले के साथ नजर नहीं आया था। अंतरराष्ट्रीय मंच पर ये मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत का ही नतीजा है कि सबने इसे भारत का अंदरूनी मामला बता दिया। बीते दो सालों में जम्मू-कश्मीर में आंतरिक शांति स्थायी हुई है और आतंक की घटनाएं भी नहीं के बराबर रही हैं। इससे यही साबित हुआ है कि जम्मू-कश्मीर में होती रही घटनाओं के पीछे पाकिस्तान का हाथ रहा है।

भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर युद्धविराम लागू होना इस दौर की एक अन्य उपलब्धि है। ऐसे में अगर जम्मू-कश्मीर में बिना किसी विरोध के राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने में मोदी सरकार कामयाब हो जाती है, तो इसे अनुच्छेद 370 हटाने की सफल राजनीतिक पहल के तौर पर देखा जाएगा। परिसीमन के बहाने राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने की पहल केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक में हासिल कर ली है। सर्वदलीय बैठक में किसी दल ने इस पर कोई ऐतराज भी नहीं जताया। इससे यह भी साफ हो गया कि जम्मू-कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा देने की बात पर सभी दल सहमत हैं। बीजेपी ने भी इसे 'वक्त आने पर' सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया है। रही बात राजनीतिक बंदियों की तो यह काम केंद्र सरकार जब चाहे तब कर सकती है। मगर, इसके लिए भी वह वक्त का इंतजार करना चाहती है।

सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 पर जब कभी सुनवाई होगी तो केंद्र सरकार के सद्भावनापूर्ण प्रयासों और मकसद का सबूत यह सर्वदलीय बैठक भी होगी। जम्मू-कश्मीर के नेताओं की नजरबंदी, अन्य बंदियों की रिहाई, लंबा लॉकडाउन, इंटरनेट सेवा के ठप होने जैसी बातों पर जवाब देने के लिए केंद्र के पास वर्तमान हालात का ब्योरा होगा। केंद्र सरकार अपने सभी कदमों का बचाव वर्तमान सुधरते हालात को पेश करते हुए कर सकेगी। इसमें संदेह नहीं कि अब जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों की कमर टूट चुकी है। अलगाववादियों को जनसमर्थन भी पहले की तरह नहीं रहा। वे अलग-थलग पड़ चुके हैं। यह सही समय है कि जब राजनीतिक प्रक्रिया को शुरू कर युवाओं के हाथों में नेतृत्व सौंपा जाए। देखना यह है कि यह काम कितनी जल्द शुरू हो पाता है क्योंकि ऐसा होते ही जम्मू-कश्मीर में एक नये अध्याय की शुरु आत हो जाएगी।

वैश्विकी

भारत-तालिबान संवाद

डॉ. दिलीप चौबे

अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके प्रतिद्वंद्वी एवं सहयोगी अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ वाशिंगटन में शुक्रवार को 'विदाई' मुलाकात की। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी अगले कुछ महीनों में पूरी होने वाली है।

इसके पहले अफगान नेताओं ने बाइडेन प्रशासन के साथ देश की मौजूदा हालात और भविष्य के संभावित घटनाक्रम पर विचार-विमर्श किया। अफगानिस्तान में अमेरिका के सैनिक हस्तक्षेप और बीस साल तक वहां अमेरिकी सेनाओं की मौजूदगी के बाद किसको क्या हासिल हुआ, इस पर बहस जारी है, लेकिन इतना निश्चित है कि अफगानिस्तान में पश्चिमी देशों की तर्ज पर लोकतांत्रिक प्रणाली कायम करने और वहां शांति स्थायित्व कायम करने के लक्ष्य में अमेरिका असफल रहा। बीस साल बाद भी काबुल की केंद्रीय सत्ता इस स्थिति में नहीं है कि वह पूरे देश पर हुक्मरानी कायम कर सके तथा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के जरिये शासन-प्रशासन चला सके।

तालिबान के विरुद्ध अधिकतम शक्ति प्रयोग करने के बावजूद अमेरिका इस उग्रवादी और मजहबी कट्टरपंथी रक्तबीज का उन्मूलन नहीं कर सका। आज हालात यह है कि देश के करीब एक चौथाई भूभाग पर तालिबान का कब्जा है और यह आशंका बरकरार है कि वे काबुल पर काबिज हो सकते हैं। अफगानिस्तान से जुड़े विभिन्न पक्ष और पड़ोस के देशों में यह आशा जरूर है कि इस दो दशक के घटनाक्रम से तालिबान ने भी कुछ सीखा होगा। देश में जो विकास गतिविधियां हुई हैं और सकारात्मक बदलाव आए हैं, उसे सुरक्षित रखने में तालिबान का भी हित है।

तालिबान नेतृत्व की ओर से भी कुछ ऐसे संकेत मिले हैं कि वह अपने रवैये में लचीलापन ला रहा है। संभवतः यही कारण है कि भारत में तालिबान के नेताओं के साथ परोक्ष रूप से संपर्क संवाद कायम करने का सिलसिला शुरू किया है। ऐसी चर्चा है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस संपर्क-संवाद से जुड़े रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने तालिबान के साथ बातचीत की। स्पष्ट रूप से पुष्टि नहीं की है। हालांकि उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान से जुड़े सभी पक्षों के साथ भारत संपर्क में है।

खाड़ी का देश कतर भारत और तालिबान के बीच संपर्क का माध्यम बन रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल में कतर के विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर विचार-विमर्श किया है। कतर के सूत्रों के अनुसार भारत और तालिबान के बीच संपर्क और बातचीत हुई है।

अफगानिस्तान के बारे में भारत की मुख्य चिंता यह है कि वहां तालिबान का वर्चस्व कायम न हो। विशेषकर ऐसा तालिबान नेतृत्व जो पाकिस्तान के इशारे पर चलता हो। विदेश मंत्रालय ने आशा व्यक्त की है कि अफगान लोग खुद इस बात का लेखा-जोखा लेंगे कि किस देश ने उन्हें क्या दिया।

भारत ने अफगानिस्तान को स्कूल, अस्पताल, सड़क सहित आधारभूत ढांचा और स्थानीय शासन के सामुदायिक केंद्र प्रदान किए हैं। दूसरी ओर पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को क्या दिया? भारत को काबुल में तालिबान की सत्ता कायम होने पर जम्मू-कश्मीर को लेकर भी चिंता है। इस प्रदेश में दो वर्ष के दौरान बहुत सकारात्मक बदलाव आए हैं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कश्मीरी नेताओं के साथ बातचीत की पहल पर भावी रोडमैप पर भी चर्चा की है। भारत कभी यह नहीं चाहेगा कि उसे पाकिस्तान या अफगानिस्तान की ओर से सीमा पार आतंकवाद के खतरों का सामना करना पड़े।

चीन को भी अपने शिक्यांग प्रांत में अफगानिस्तान की ओर से सीमा पार आतंकवाद का खतरा है। हालांकि पाकिस्तान उसके प्रभाव में है और इस्लामाबाद तालिबान को चीन के साथ छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं देगा। कुछ ही दिन पहले शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में आतंकवाद विरोधी नीति पर चर्चा हुई। आशा की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों शंघाई सहयोग संगठन अफगानिस्तान में आतंकवाद और उग्रवाद के विरुद्ध कारगर कदम उठाएगा तथा वहां शांति तथा स्थायित्व की स्थापना का जिम्मा लेगा।

बतंगड़ बेतुक

या खुदा पिटाई तो धर्मनिरपेक्ष निकली

विभांशु दिव्याल

झल्लन बोला, 'ददाजू, जो हुआ सो हुआ, पर जो हुआ वह अच्छा नहीं हुआ।' हमने कहा, 'अब ऐसा क्या हो गया जो तेरे दिमाग ने फिर से अच्छा-बुरा कर दिया, किसी ने कुछ कह-सुन दिया या तुझे भौतिक तौर पर धुन दिया?'

झल्लन बोला, 'आप भी ना ददाजू, सिर्फ हमारी धुनाई की ही सोचते हो, हमें लेकर सिर्फ हवा में ही अपनी बात रोपते हो। हम इस वक्त अपनी पर नहीं आ रहे हैं, हम तो जो हमारे पहलवान इदरीश उम्मेद पर बीती है वह बता रहे हैं, बताइए, उसने ऐसा क्या नया जुर्म कर दिया जो पुलिस ने उसे फालतू में धर लिया।' हमने कहा, 'तो तू उम्मेद पहलवान की बात कर रहा है, उसे तो उसके अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है पर तू यूं ही इमोशनल हुआ जा रहा है।' झल्लन बोला, 'एक पिटे हुए बुजुर्ग की तरफदारी करना कौन सा गुनाह है, बताइए ददाजू, इसके बारे में आपकी क्या सलाह है?' हमने कहा, 'तेरा यह पहलवान एक मुस्लिम बुजुर्ग की असभ्य पिटाई के बारे में असलियत छिपाकर पूरी दुनिया को जो भी बता रहा था वह गलत बता रहा था, इस पिटाई पर साम्प्रदायिकता का मुलम्मा चढ़ा रहा था, मुसलमानों को भड़का रहा था, साम्प्रदायिक नफरत को बढ़ाकर आपसी सौहार्द से बनी हमारे लोकतंत्र की बुनियाद को हिला रहा था।'

झल्लन बोला, 'काहे छोटी-छोटी बातों में लोकतंत्र को घसीट लाते हो, काहे बेचारे की बुनियाद हिलाते हो। हमारा पहलवान तो अपनी राजनीति चमका रहा था, अपनी सुन्नत पर खतरा महसूस कर अपनी कौम को जगा रहा था, हमारे कटदाढ़ी बुजुर्ग समद ने अपनी पिटाई के बारे में जो उसे बताया वही वह लाइव वीडियो के जरिए दुनिया को बता रहा था, और इन सबके जरिए अपनी समाजवादी पार्टी के लिए आदर्श और अद्भुत समाजवाद ला रहा था।' हमने कहा, 'धर्मनिरपेक्षता की भी हद होती है झल्लन, जो तू गलत को सही बताए जा रहा है और पहलवान के पक्ष में परचम उठाए जा रहा है। तेरा यह समाजवादी पहलवान वह नहीं कह रहा था जो बुजुर्ग कह रहा था, यह पहलवान वह कह रहा था जो वह बुजुर्ग से कहलवा रहा था। बुजुर्ग ने अपने पहले बयान में पूरे कांड को अपना अपहरण बताया, हमलावरों को अज्ञात बताया, अपनी दाढ़ी काटे जाने को उसने एक मुसलमान के प्रति हिंदुओं का अत्याचार दिखाया और अगले बयान में उसने अपहरणकर्ताओं पर पिटाई के साथ-साथ जय श्रीराम का नारा लगवाने का आरोप भी लगाया। उसने जितनी बार भी बयान दिये, हर बयान में कुछ-न-कुछ अंतर जरूर आया। कुल मिलाकर यह फैसला कर लिया गया कि हिंदू उन्मादियों ने एक सीधे-सरल मुस्लिम बुजुर्ग के साथ वहशियाना बर्ताव किया और इस बुजुर्ग को न्याय दिलाने का बीड़ा हमारे समाजवादी पहलवान सहित तत्काल कुछ मुस्लिम, कुछ सेक्युलर और कुछ समाजवादी बुद्धिजीवियों ने उठा लिया।'

झल्लन बोला, 'इसमें नया क्या हुआ ददाजू, यह तो अब एक चलन है जिस पर उंगली उठाना बेकार है, इस चलन के चलते आपका हर आरोप निराधार है।' हमने कहा, 'निराधार नहीं, हमारी हर बात का आधार है और हमारी समझ से यह नफरत फैलाने का घृणित व्यापार है।' झल्लन बोला, 'नहीं ददाजू, सोचिए, हमारे पहलवान भाई ने कहा कि उसने यह प्रपंच राजनीतिक लाभ के लिए रचा था क्योंकि अपनी राजनीति चमकाने के लिए बुजुर्ग की पिटाई का एक बड़ा मौका उसके हाथ लगा था। अब वह बेचारा फिरकापरस्ती, साम्प्रदायिकता, नफरत जैसी छोटी-मोटी बातों पर रोक लगाने पर विचार करे या कि अपनी समाजवादी राजनीति के लिए इनका जमकर इस्तेमाल करे?' हमने कहा, 'लेकिन पड़ताल में क्या पाया गया? बुजुर्ग के बदलते बयानों का झूठ सामने आया, मुसलमानों को भड़काने का तेरे पहलवान का षड़यंत्र सामने आया और इस घटना को हिंदू-मुस्लिम रंग देने वाले कथित बुद्धिजीवियों का कुत्सित साम्प्रदायिक अभियान नजर आया। और अब तो यह खुलकर सामने आ गया है कि बुजुर्ग की पिटाई साम्प्रदायिक नहीं बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष पिटाई थी, जिसमें हिंदू-मुसलमान दोनों सम्प्रदायों ने सौहार्दपूर्ण सहयोग किया था मगर स्वयं बेचारे धर्मनिरपेक्षों ने इस धर्मनिरपेक्ष पिटाई को साम्प्रदायिक कर दिया था, इसमें मजहबी जहर भर दिया था।'

झल्लन बोला, 'यहीं तो सारा खेल बिगड़ गया, एक बना-बनाया सुविचारित प्लान उजड़ गया। हमारे पहलवान जी पिटाई को धार्मिक बनाकर राजनीति करना चाहते थे सो नहीं कर पाये और पहलवान जी के हमदर्द कथित बुद्धिविरोधजीवी अपनी वाह-वाह से अपनी झोली नहीं भर पाये।' हमने कहा, 'इस तरह की साम्प्रदायिक नफरत फैलाकर ये लोग पहले से ही जहरीले वातावरण को और अधिक जहरीला कर देंगे और जो लोग अभी भी थोड़ा सद्भाव और सौहार्द्र रखते हैं उनके दिमाग में भी जहर भर देंगे।' झल्लन बोला, 'काहे चिंता करते हो ददाजू, इन्हें जो करना है वो तो ये करते-कराते रहेंगे, कोई भी पिटाई कितनी भी धर्मनिरपेक्ष क्यों न हो उसे धर्मसापेक्ष बनाते रहेंगे। आखिर ये लोकतंत्र इसी तरह की राजनीति के लिए है सो ये लोग लोकतंत्र की खातिर इसी तरह की राजनीति करते रहेंगे और हम सेक्युलर लोग इनका साथ देते रहेंगे। बस, आगे यह ध्यान रखेंगे कि जिस पिटाई पर उन्मादी अभियान चलाया जाये वह ससुरी कहीं धर्मनिरपेक्ष न निकल आये, हमारी किरकिरी न कर जाये।'

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

एफपीआई ने जून में भारतीय बाजारों में 12,714 करोड़ रुपए डाले

नई दिल्ली :

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने जून में भारतीय बाजारों में शुद्ध रूप से 12,714 करोड़ रुपए डाले हैं। इससे पिछले दो माह के दौरान वे शुद्ध बिकवाल बने रहे थे। मई में एफपीआई ने भारतीय बाजारों से 2,666 करोड़ रुपए और अप्रैल में 9,435 करोड़ रुपए निकाले थे। डिपॉजिटरी सेवा कंपनियों के आंकड़ों के अनुसार, एक से 25 जून के दौरान एफपीआई ने शेयरों में 15,282 करोड़ रुपए डाले। इस दौरान उन्होंने ऋण या बांड बाजार से 2,568 करोड़ रुपए निकाले। इस तरह उनका शुद्ध निवेश 12,714 करोड़ रुपए रहा। बजाज कैपिटल के संयुक्त चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक संजीव बजाज ने कहा कि जून में भारतीय बाजारों में प्रवाह अनुकूल वैश्विक संकेतकों तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के परिदृश्य में सुधार की वजह से बढ़ा है। कोविड-19 के मामलों में कमी के बीच अंकुशों में ढील दी गई है तथा टीकाकरण की रफ्तार भी बढ़ी है।

कोटक सिक्योरिटीज के कार्यकारी उपाध्यक्ष (इक्विटी तकनीकी अनुसंधान) श्रीकान्त चौहान ने कहा कि कुल मिलाकर इस सप्ताह एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स करीब 1.49 प्रतिशत बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस महीने आज की तारीख तक भारत और इंडोनेशिया को छोड़कर अन्य उभरते तथा एशियाई बाजारों से एफपीआई ने निकासी की है।

वैश्विक आर्थिक सुधार भारत के लिए सकारात्मक : ईवाई

नई दिल्ली। कंसल्टेंसी फर्म ईवाई का कहना है कि मौजूदा दौर में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए वैश्विक आर्थिक सुधार सकारात्मक है। अपनी आर्थिक पल्स रिपोर्ट में, कंसल्टेंसी फर्म ने कहा, भारत के निर्यात ने अच्छा प्रदर्शन करना जारी रखा है। भारत के माल का कुल निर्यात मई 2020 में 59 प्रतिशत बढ़ा है और अप्रैल 2020 की तुलना में स्थिर रहा है। कोविड की दूसरी लहर के कारण भारत में सेवाओं का निर्यात अप्रैल में प्रभावित हुआ, और मई में केवल मामूली वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, सेवा निर्यात अभी भी मई 2020 की तुलना में 6 प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि, अप्रैल 2021 की तुलना में मई में भारत के गैर-तेल सामानों के कुल आयात में 17 प्रतिशत की कमी आई है। यह घरेलू बाजार में सुस्त मांग को दर्शाता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आई रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल 2021 में उर्वरक बिक्री में अप्रैल 2020 की तुलना में गिरावट आई है। इसके अलावा, अप्रैल और मई 2021 में ट्रैक्टर की बिक्री में भारी गिरावट आई है। इससे कोविड-19 का संक्रमण फैलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रभावित होने का जोखिम उजागर होता है।

मई में भारत का सोने का आयात बढ़ा, चांदी के आयात में गिरावट

नई दिल्ली। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, मई में 679.16 मिलियन डॉलर (4,976.07 करोड़ रुपये) के सोने का आयात किया गया। यह देशव्यापी लॉकडाउन के बीच पिछले साल मई में आयातित 76.31 मिलियन डॉलर मूल्य के सोने से कई गुना ज्यादा है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 22 की अप्रैल-मई अवधि के लिए, पीली धातु का आयात 6.91 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के दौरान 79.14 मिलियन डॉलर मूल्य के सोने के मुकाबले था। हालांकि मांग में सुधार के साथ सोने के आयात में सुधार हुआ है, दूसरी ओर चांदी के आयात में कमी आई है। पिछले महीने 15.66 मिलियन डॉलर की चांदी का आयात किया गया, जो साल-दर-साल आधार पर 95.3 प्रतिशत कम है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 22 में अब तक 27.56 मिलियन डॉलर मूल्य की चांदी का आयात किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए आयात से लगभग 94 प्रतिशत कम है। दूसरी ओर, साल-दर-साल आधार पर मौजूदा वित्तीय वर्ष के अप्रैल-मई की अवधि के दौरान भारत से रत्न और आभूषण का निर्यात कई गुना बढ़कर 6.34 बिलियन डॉलर हो गया। मई में, रत्न और आभूषण निर्यात मई वित्त वर्ष 21 में 1.06 बिलियन डॉलर से बढ़कर लगभग 3 बिलियन डॉलर हो गया।

आरबीआई को मल्टीमीडिया जन-जागरूकता अभियान के लिए विज्ञापन एजेंसी की तलाश

मुंबई

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) अपने नियमों के बारे में सर्व-सामान्य को उनकी अपनी भाषा में जागरूक करने का अभियान तेज करने के लिए ऐसी कंपनी की तलाश कर रहा है, जो 14 भाषाओं में उसके लिए मल्टीमीडिया (विभिन्न माध्यमों लायक) प्रचार सामग्री तैयार कर सके। आरबीआई का यह अभियान अंग्रेजी के अलावा हिंदी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषा में चलाया जाएगा। आरबीआई के एक दस्तावेज के अनुसार इस अभियान में जन संचार के परम्परागत और नए , हर प्रकार के माध्यम का उपयोग किया जाएगा। इसमें समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन चैनलों और सिनेमा हॉल के अलावा अभियान में डिजिटल मीडिया, वेब पोर्टल और सोशल मीडिया को भी शामिल किया जाएगा। केंद्रीय बैंक ने जागरूकता अभियान की रचनात्मक रुप-रेखा तैयार करने के लिए विज्ञापन एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित किए है। आरबीआई के अनुसार जन जागरूकता अभियान पूर्ण मल्टीमीडिया, बहुभाषी, अखिल भारतीय स्तर के होंगे। जिनका उद्देश्य देशभर में लोगों को आरबीआई के नियमों और अन्य पहलों के बारे में सामान्य जागरूकता पैदा करना है। केंद्रीय बैंक 'आरबीआई कहता है' नाम से एक मीडिया अभियान भी चलाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को उसके विनियमों के बारे में जानकारी देना और बैंकों में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाना है।

सेंसेक्स की टॉप-10 में से 6 कंपनियों का मार्केट कैप 1.11 लाख करोड़ रुपए बढ़ा

बिजनेस डेस्क :

सेंसेक्स की शीर्ष 10 में से छह कंपनियों के बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) में बीते सप्ताह 1,11,220.5 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। इस दौरान सबसे अधिक लाभ में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) तथा इन्फोसिस रहीं। समीक्षाधीन सप्ताह में टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बाजार पूंजीकरण में बढ़ोतरी हुई। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर लि., बजाज फाइनेंस और कोटक महिंद्रा बैंक का बाजार मूल्यांकन घट गया। बीते सप्ताह टीसीएस का बाजार पूंजीकरण 30,961.06 करोड़ रुपए बढ़कर 12,50,538.30 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इन्फोसिस का बाजार मूल्यांकन 29,807.59 करोड़ रुपए बढ़कर 6,70,915.93 करोड़ रुपए रहा। एचडीएफसी बैंक की बाजार हैसियत 19,838.88 करोड़ रुपए के उछाल के साथ 8,36,426.69 करोड़ रुपए पर और एसबीआई की 14,234.76 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी के साथ 3,82,642.72 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। आईसीआईसीआई बैंक का बाजार पूंजीकरण 12,775.99 करोड़ रुपए बढ़कर 4,49,166.77 करोड़ रुपए पर और एचडीएफसी का 3,602.22 करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ 4,52,778.40 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इस रुख के उलट रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार मूल्यांकन 76,548.77 करोड़ रुपए घटकर 13,34,009.02 करोड़ रुपए पर आ गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर का बाजार पूंजीकरण 7,424.7 करोड़ रुपए घटकर 5,75,449.55 करोड़ रुपए और कोटक महिंद्रा बैंक का 5,084.82 की गिरावट के साथ 3,43,934.41 करोड़ रुपए पर आ गया। बजाज फाइनेंस की बाजार हैसियत 763.55 करोड़ रुपए घटकर 3,66,662.44 करोड़ रुपए रह गई। शीर्ष 10 कंपनियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले स्थान पर कायम रही। उसके बाद क्रमशः टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, बजाज फाइनेंस और कोटक महिंद्रा बैंक का स्थान रहा। बीते सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 580.59 अंक या 1.10 प्रतिशत के लाभ में रहा।

गुड़गांव मेट्रो परियोजना - कंपनी को हरियाणा सरकार से मिले 1,925 करोड़ रुपये

नई दिल्ली। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएल एंड एफएस) को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) से गुड़गांव मेट्रो प्रोजेक्ट मामले में अंतरिम टर्मिनेशन भुगतान के रूप में 1,925 करोड़ रुपये मिले हैं। एस्क्रो खातों में विधिवत प्राप्त यह भुगतान 26 मार्च, 2021 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आता है, जिसके तहत गुड़गांव मेट्रो प्रोजेक्ट में आईएल एंड एफएस के पक्ष में फैसला सुनाया गया था उक्त एस्क्रो खातों से किसी भी राशि का विनियोग आदेश के अनुसार एनसीएलएटी या किसी अन्य सक्षम कानूनी प्राधिकारी के आगे के आदेशों के अधीन होगा, जिसका आईएल एंड एफएस द्वारा विधिवत अनुपालन किया जाएगा। फैसले के हिस्से के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने एचएसवीपी को दो एसपीवी के एस्क्रो खातों में तीन महीने के भीतर कुल देय राशि (कैग द्वारा किए गए 2,400 करोड़ रुपये से अधिक के आधार पर ऑडिट) का 80 प्रतिशत जमा करने का निर्देश दिया था, जो कि 1,925 करोड़ रुपये है। आरएमजीएल में आंध्रा बैंक अन्य पीएनबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और देना बैंक (वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा) के साथ अग्रणी बैंक है। आरएमजीएसएल में केनरा बैंक अन्य बैंकों जैसे कि आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक (वर्तमान में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया), पंजाब एंड सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड के साथ अग्रणी बैंक है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, 26 मार्च, 2021 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके बाद एचएसवीपी के आदेश का अनुपालन और आईएल एंड एफएस समूह की संस्थाओं को देय राशि का हस्तांतरण, भारतीय बुनियादी ढांचा क्षेत्र में हितधारकों और ऋणदाताओं के हितों की रक्षा करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। प्रवक्ता ने कहा कि यह निर्णय अन्य परियोजनाओं के लिए भी एक मिसाल कायम करेगा, जिसमें आईएल एंड एफएस सहित बुनियादी ढांचा कंपनियां अपने वैध बकाये का भुगतान और विभिन्न राज्य सरकारों के साथ वैध अनुबंधों और रियायत समझौतों को लागू करने की मांग कर रही हैं।

वृहद आर्थिक आंकड़ों, टीकाकरण की रफ्तार, वैश्विक रुख से तय होगी बाजार की दिशा

मुंबई :

घरेलू शेयर बाजार गिरावट से उबरते हुए बीते सप्ताह नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। आने वाले सप्ताह में निवेशकों का रुख बहुत हद तक विदेशी बाजारों से प्रभावित रहने की संभावना है। साथ ही घरेलू स्तर पर कोविड-19 की स्थिति का असर भी बाजार पर दिखेगा। बीएसई का सेंसेक्स 580.59 अंक यानी 1.11 प्रतिशत की साप्ताहिक बढ़त के साथ सप्ताहांत पर शुक्रवार को 52,925.04 अंक के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। इस दौरान बुधवार को छोड़कर शेष चार दिन बाजार में बढ़त रही। मंगलवार को बीच कारोबार में यह पहली बार 53 हजार अंक को पार करता हुआ 53,057.11 अंक के शिखर को छूने में भी कामयाब रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में सोमवार और बुधवार को गिरावट रही। अन्य तीन दिन यह बढ़त में बंद हुआ। पूरे सप्ताह के दौरान 177 अंक यानी 1.13 अंक चढ़कर शुक्रवार को यह 15,860.35 अंक पर बंद हुआ। घरेलू स्तर पर इस सप्ताह बुनियादी आठ उद्योग क्षेत्रों के आंकड़े आने हैं। इसके अलावा विनिर्माण क्षेत्र के पीएमआई आंकड़े भी जारी होने हैं। निवेशकों की नजर कोविड-19 के मामलों पर भी होगी। मझौली और छोटी कंपनियों में निवेशकों का विश्वास अधिक रहा। बीएसई का मिडकैप 311.44 अंक यानी 1.40 प्रतिशत चढ़कर सप्ताहांत पर 22,549.65 अंक पर और स्मॉलकैप 347.40 अंक यानी 1.41 प्रतिशत की तेजी के साथ 24,996.23 अंक पर पहुंच गया। दोनों सूचकांक बुधवार और गुरुवार को छोड़कर शेष तीन दिन बढ़त में रहे। समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान सेंसेक्स की 30 में से 22 कंपनियों के शेयरों में तेजी और शेष आठ में गिरावट रही। वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी का शेयर सर्वाधिक 9.84 प्रतिशत की साप्ताहिक बढ़त में रहा। अन्य वाहन निर्माता कंपनियों में महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर 1.56 फीसदी और बजाज ऑटो का 0.75 फीसदी चढ़ा। सेंसेक्स में पिछले सप्ताह दुबारा शामिल होने वाली टाटा स्टील का शेयर 6.75 प्रतिशत मजबूत हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सेंसेक्स में सबसे अधिक 5.43 प्रतिशत का नुकसान उठाया। आईटी एवं टेक क्षेत्र की इंफोसिस का शेयर 4.65 प्रतिशत, टीसीएस का 2.54 प्रतिशत, एचसीएल टेक्नोलॉजीज का 2.08 प्रतिशत और टेक महिंद्रा का 1.73 प्रतिशत मजबूत हुआ। बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों में बजाज फाइनेंस में 4.09 फीसदी, भारतीय स्टेट बैंक में 3.86 फीसदी, एक्सिस बैंक में 3.37 फीसदी, आईसीआईसीआई बैंक में 2.92 फीसदी, एचडीएफसी बैंक में 2.32 फीसदी, इंडसइंड बैंक में 1.79 फीसदी और एचडीएफसी में 0.80 फीसदी की तेजी रही जबकि कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर 1.46 प्रतिशत और बजाज फाइनेंस का 0.21 प्रतिशत लुढ़क गया। दवा कंपनियों में सनफार्मा का शेयर 0.57 प्रतिशत और डॉ. रेड्डीज लैब का 0.51 प्रतिशत चढ़ा। एफएमसीजी कंपनियों में मिश्रित रुख रहा। हिंदुस्तान यूनिलिवर में 1.27 फीसदी और नेस्ले इंडिया में एक फीसदी की गिरावट रही जबकि आईटीसी का शेयर 0.22 प्रतिशत मजबूत हुआ। अन्य कंपनियों में अल्ट्राटेक सीमेंट 3.41 प्रतिशत, एलएंडटी 3.21 प्रतिशत, टाइटन 2.72 प्रतिशत और एनटीपीसी 2.20 प्रतिशत की साप्ताहिक बढ़त में बंद हुआ। एशियन पेंट्स का शेयर 1.52 फीसदी, पावरग्रिड का 0.92 प्रतिशत और भारती एयरटेल का 0.72 फीसदी लुढ़क गया।

बुनियादी ढांचा क्षेत्र की 478 परियोजनाओं की लागत 4.4 लाख करोड़ रुपए बढ़ी

नई दिल्ली :

बुनियादी ढांचा क्षेत्र की 150 करोड़ रुपए या इससे अधिक के खर्च वाली 478 परियोजनाओं की लागत में तय अनुमान से 4.4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी मिली है। देरी और अन्य कारणों की वजह से इन परियोजनाओं की लागत बढ़ी है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय 150 करोड़ रुपए या इससे अधिक लागत वाली बुनियादी ढांचा क्षेत्र की परियोजनाओं की निगरानी करता है। मंत्रालय की मई-2021 की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह की 1,768 परियोजनाओं में से 478 की लागत बढ़ी है, जबकि 525 परियोजनाएं देरी से चल रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, ''इन 1,768 परियोजनाओं के क्रियान्वयन की मूल लागत 22,86,955.18 करोड़ रुपए थी, जिसके बढ़कर 27,27,220.47 करोड़ रुपए पर पहुंच जाने का अनुमान है। इससे पता चलता है कि इन परियोजनाओं की लागत 19.25 प्रतिशत या 4,40,265.29 करोड़ रुपए बढ़ी है।'' रिपोर्ट के अनुसार, मई-2021 तक इन परियोजनाओं पर 13,30,533.53 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जो कुल अनुमानित लागत का 48.79 प्रतिशत है। हालांकि, मंत्रालय का कहना है कि यदि परियोजनाओं के पूरा होने की हालिया समयसीमा के हिसाब से देखें, तो देरी से चल रही परियोजनाओं की संख्या कम होकर 387 पर आ जाएगी। रिपोर्ट में 995 परियोजनाओं के चालू होने के साल के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देरी से चल रही 525 परियोजनाओं में 100 परियोजनाएं एक महीने से 12 महीने की, 124 परियोजनाएं 13 से 24 महीने की, 182 परियोजनाएं 25 से 60 महीने की तथा 119 परियोजनाएं 61 महीने या अधिक की देरी में चल रही हैं। इन 525 परियोजनाओं की देरी का औसत 46.36 महीने है। इन परियोजनाओं की देरी के कारणों में भूमि अधिग्रहण में विलंब, पर्यावरण व वन विभाग की मंजूरियां मिलने में देरी तथा बुनियादी संरचना की कमी प्रमुख हैं।

भारत सरकार से वसूली को एयर इंडिया के बाद कई और सरकारी कंपनियां केयर्न के निशाने पर

बिजनेस डेस्क :

भारत सरकार से अपने बकाया की वसूली के लिए ब्रिटेन की केयर्न एनर्जी पीएलसी की निगाह अब एयर इंडिया के बाद अमेरिका से लेकर सिंगापुर तक सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य कंपनियों तथा बैंकों की संपत्तियों पर है। पिछली तारीख से कर मामले में मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने केयर्न के पक्ष में फैसला दिया है, जिसके बाद उसे भारत सरकार से वसूली करनी है। कंपनी के एक अधिवक्ता ने कहा कि केयर्न कई देशों में मुकदमा दायर करेगी, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को भारत सरकार पर बकाया 1.2 अरब डॉलर के साथ ब्याज और जुर्माने के भुगतान के लिए 'जिम्मेदार' बनाया जा सके।

पिछले महीने केयर्न ने न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी जिला अदालत में मुकदमा दायर किया था। केयर्न ने कहा था कि एयर इंडिया पर भारत सरकार का नियंत्रण है। ऐसे में एयरलाइन पर पंचनिर्णय के तहत भुगतान का दायित्व बनता है।

कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रही विधि कंपनी क्लिन इमैनुअल उर्कहार्ट एंड सुलिवन के सॉवरेन लिटिगेशन प्रैक्टिस प्रमुख डेनिस हर्निटजकी ने कहा, ''कई ऐसे सार्वजनिक उपक्रम हैं जिन पर हम प्रवर्तक कार्रवाई का विचार रहे है। प्रवर्तन कार्रवाई जल्द होगी और शायद यह अमेरिका में नहीं हो। तीन सदस्यीय अंतराष्ट्रीय पंचाट ने पिछले साल दिसंबर में एकमत से केयर्न पर भारत सरकार की पिछली तारीख से कर मांग को खारिज कर दिया था। न्यायाधिकरण में भारत की ओर से नियुक्त एक जज भी शामिल थे। न्यायाधिकरण ने सरकार को उसके द्वारा बेचे गए शेयरों, जब्त लाभांश और कर रिफंड को वापस करने का निर्देश दिया था।

चार साल के दौरान पंचनिर्णय प्रक्रिया में शामिल रहने के बावजूद भारत सरकार ने इस फैसले को स्वीकार नहीं किया था और न्यायाधिकरण की सीट-नीदरलैंड की अदालत में इसे चुनौती दी थी।

अपने शेयरधारकों के दबाव के बाद केयर्न विदेशों में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ओर बैंक खातों को जब्त कर इस राशि की वसूली का प्रयास कर रही है। हर्निटजकी ने कहा, ''पंच निर्णय को कई देशों में पंजीकृत किया जाएगा या जल्द मान्य किया जाएगा। अपने अंतरराष्ट्रीय शेयरधारकों का मूल्य निकालने के लिए केयर्न दुनिया भर के देशों में प्रवर्तन की कार्रवाई को तेज करेगी।''

प्रस्तावित ई-कॉमर्स नियमों के नकारात्मक प्रभाव को लेकर चिंतित हैं कुछ राज्य

नयी दिल्ली,

कुछ राज्यों ने केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए ई-कॉमर्स नियमों को लेकर चिंता जताई है। इनमें ज्यादातर गैर-भाजपा शासित राज्य है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने गलत तथ्यों की जानकारी देकर अपने उत्पाद बेचने तथा धोखाधड़ी के तरीके से छूट पर अंकुश लगाने के लिए इन नियमों का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित नियमों पर आपत्ति जताने वाले राज्यों का कहना है कि इससे रोजगार पर नकारात्मक असर पड़ेगा। साथ ही इससे हाल के वर्षों में विभिन्न मंचों द्वारा एमएसएमई को पहुंच उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई व्यवस्था भी प्रभावित होगी। इन राज्यों सरकारों की योजना प्रस्तावित नियमों में मजबूत रक्षोपाय उपायों का सुझाव देने की है, जिससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 में किसी बदलाव से उनकी आर्थिक वृद्धि और राजस्व संग्रहण प्रभावित नहीं होगा। सूत्रों ने कहा कि इसके साथ यह भी ध्यान रखा जाएगा कि उनके सुझाव प्रस्तावित नियमों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण ढांचे को बेहतर करने के रास्ते में किसी तरह बाधक नहीं बनें। इन अधिकारियों ने अपना नाम न बताने की शर्त पर कहा कि यह संवेदनशील मामला है और इससे सावधानी से निपटने की जरूरत है, क्योंकि उपभोक्ता हितों के संरक्षण के साथ रोजगार, एसएमएसई तथा स्वरोजगार में लगे लोगों का बचाव भी बेहद जरूरी है। अधिकारियों ने कहा कि नियमों के मसौदे पर औपचारिक सुझाव केंद्र को सौंपे जाएंगे। केंद्र ने इस मुद्दे पर छह जुलाई तक टिप्पणियां मांगी हैं।ई-कॉमर्स कंपनियों में निवेश करने वाले विदेशी और घरेलू निवेशकों तथा अन्य कारोबारी इकाइयों ने भी प्रस्तावित नियमों को लेकर आशंका जताई है। विशेष रूप से ई-कॉमर्स कंपनियों में निवेश करने वाले निवेश 'फ्लॉल-बैक लायबिलिटी', फ्लैश सेल्स या भारी रियायत तथा डाटा शेयरिंग के बारे में नियमों को लेकर आशंकित हैं।

मोबाइल पेमैंट करने वाली बड़ी कंपनियों पर शिकंजा कसेगा चीन

मुंबई ।

जैक मा पर शिकंजा कसने के बाद अब चीन की सत्ता पर काबिज कम्युनिस्ट पार्टी ने मोबाइल पेमैंट करवाने वाली बड़ी वित्तीय आई.टी. कंपनियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। चीन आई.टी. कंपनियों पर नियंत्रण के लिए नीति बदलने जा रहा है और नई नीति के तहत बड़ी आई.टी. कंपनियों में सरकार का एक प्रतिनिधि कंपनी के बोर्ड में शामिल किया जाएगा जो कंपनी की वित्तीय गतिविधियों पर नजर रखेगा। जैक मा पर शिकंजा कसे जाने के बाद चीन की बड़ी आई.टी. कंपनियों जे.डी.डिजिट्स, टेनसेंट, बाइडू और लुफैक्सको भी वित्तीय रूप से नुक्सान हुआ है क्योंकि अब ये कंपनियां भी सीधा सरकार की निगरानी में आ रही हैं और कंपनियों से कहा जा रहा है कि उन्हें अपना वित्तीय ढांचा बदलना पड़ेगा। इसके साथ ही कंपनियों के वित्तीय लेन-देन की निगरानी और कंज्यूमर डाटा पर नजर रखने के लिए कंपनियों में बैंक आफ चाइना के अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है। दरअसल ऐंट ग्रुप के मालिक जैक मा ने 8 महीने पहले सार्वजनिक मंच पर चीन की सरकार की नीतियों की आलोचना कर दी थी और कहा था कि चीनी वित्तीय संस्थाएं 'कठपुतली दुकानों' जैसी हो गई हैं और उनके पास कोई इनोवेटिव आइडिया नहीं है। जैक मा के इस बयान के बाद चीन ने उन पर शिकंजा कसना शुरू किया और चीनी वित्तीय नियामक आई.पी.ओ. को लॉन्च होने से रोक दिया। इनवैस्टर्स ग्रुप होर्मिंगा सिक्योरिटीज के हांगकांग और शंघाई स्टॉक एक्सचेजों पर आने वाले आई.पी.ओ. को खरीदने का इंतजार कर रहे थे। यह आई.पी.ओ. करीब 34.4 अरब डॉलर का था। कुछ विश्लेषक इसे पेइचिंग के ऐंट ग्रुप जैसे विशालकाय समूहों और खुद मा की ग्रोथ पर लगाम लगाने की कोशिश के तौर पर देखते हैं।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सीमित ओवरों के लिए रोहित को कप्तान बनायें : पनेसर

लंदन । इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर ने कहा है कि सीमित ओवरों के लिए विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा को कप्तान बनाया जाना चाहये। पनेसर का मानना है कि इससे विराट पर कप्तानी का बोझ कम हो जाएगा। पनेसर के अनुसार रोहित की कप्तानी में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन बेहद अच्छा रहा है और टी-20 विश्वकप से पहले रोहित को कप्तानी दे देनी चाहिए। 'पनेसर ने कहा, 'मुझे लगता है कि टी-20 कप्तानी शायद रोहित शर्मा को दे देनी चाहिए। उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं विराट यहां दबाव में दिख रहे हैं और अगर टीम इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है और टी-20 विश्व कप 2021 गंवा देती है तो आप जानते हैं कि क्या होगा।' रोहित का रिकॉर्ड बतौर टी-20 कप्तान शानदार रहा है और मुंबई इंडियंस को अपनी अगुवाई में पांच बार चैंपियन बना चुके हैं। रोहित की कप्तानी में भारत ने निदास ट्रॉफी और एशिया कप अपने नाम किया था। डब्ल्यूटीसी के फाइनल में मिली हार के बाद विराट कोहली ने टीम में बड़े बदलाव होने के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था, 'हम एक साल तक इंतजार नहीं करेंगे। आप हमारी सीमित ओवरों की टीम देखें तो हमारे पास गहराई है और खिलाड़ी आत्मविश्वास से भरे हैं। टेस्ट क्रिकेट में भी इसकी जरूरत है।'

मोदी ने ओलंपिक के लिए चुने गए खिलाड़ियों के संघर्ष की सराहना की, उनके समर्थन का आग्रह किया

नई दिल्ली ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाले भारतीय खिलाड़ियों की सराहना करते हुए रविवार को कहा कि उन सभी ने इसके लिए 'वर्षों तक परिश्रम' किया है और देश को अगले महीने तोक्यो खेलों के दौरान उन पर दबाव डाले बिना उनका समर्थन करना चाहिए। कोरोना महामारी के कारण पिछले साल स्थगित हुए ओलंपिक का आयोजन इस साल 23 जुलाई से 8 सितंबर तक जापान की राजधानी में होगा जिसके लिए 100 से अधिक भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी जगह पक्की की है।मोदी ने 'मन की बात' के जरिए देश के संबोधन में कहा कि तोक्यो जा रहे हर खिलाड़ी का अपना संघर्ष रहा है, बरसों की मेहनत रही है। वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं जा रहें बल्कि देश के लिए जा रहे हैं। इन खिलाड़ियों को भारत का गौरव बढ़ाना है और लोगों का दिल भी जीतना है और इसलिए मेरे देशवासियों मैं आपको भी सलाह देना चाहता हूं, हमें जाने-अनजाने में भी हमारे इन खिलाड़ियों पर दबाव नहीं बनाना है, बल्कि खुले मन से, इनका साथ देना है, हर खिलाड़ी का उत्साह बढ़ाना है।'' भारत का ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2012 में लंदन खेलों में रहा था। इन खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने दो रजत सहित छह पदक जीते थे। इसके बाद रियो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी सिर्फ दो पदक जीत सके। इस संबोधन में प्रधानमंत्री ने दिग्गज फर्राटा धावक मिल्खा सिंह को भी याद किया, जिनका इस महीने कोरोन वायरस की चपेट में आने से निधन हो गया। मोदी ने कहा कि साथियों जब बात तोक्यो ओलंपिक की हो रही हो, तो भला मिल्खा सिंह जी जैसे दिग्गज एथलीट को कौन भूल सकता है। कुछ दिन पहले ही कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। जब वे अस्पताल में थे, तो मुझे उनसे बात करने का अवसर मिला था। उनसे बात करते हुए मैंने उनसे आग्रह किया था। मैंने कहा था कि आपने तो 1964 में तोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, इसलिए इस बार, जब हमारे खिलाड़ी, ओलंपिक के लिए तोक्यो जा रहे हैं, तो आपको हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाना है, उन्हें अपने संदेश से प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो खेल को लेकर इतना समर्पित और भावुक थे कि बीमारी में भी उन्होंने तुरंत ही इसके लिए हामी भर दी लेकिन दुर्भाग्य से नियति को कुछ और मंजूर था। ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने तीरंदाज दीपिका कुमारी और प्रवीण जाधव, हॉकी खिलाड़ी नेहा गोयल, मुक्केबाज मनीष कौशिक, पैदल चाल खिलाड़ी प्रियंका गोस्वामी, भालाफेंक एथलीट शिवपाल सिंह, बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग शेट्टी एवं उनके साथी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और तलवारबाज सीए भवानी देवी के जिंदगी के संघर्षों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में तो अधिकांश खिलाड़ी छोटे-छोटे शहरों, कस्बों, गांवों से निकल कर आते हैं। तोक्यो जा रहे हमारे ओलंपिक दल में भी कई ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं, जिनका जीवन बहुत प्रेरित करता है।

लुईस की अक्रामक पारी के बदौलत वेस्टइंडीज ने द.अफ्रीका को 8 विकेट से हराया

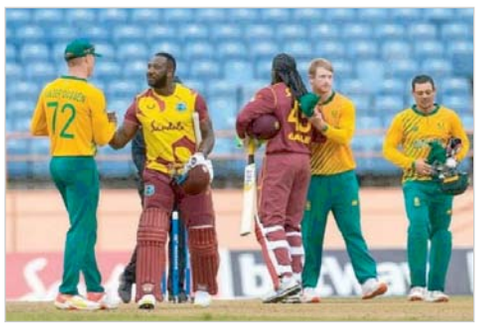

सेंट जार्ज ।

एविन लुईस के तूफानी अर्धशतक से वेस्टइंडीज ने पांच मैचों की श्रृंखला के पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 8 विकेट की आसान जीत दर्ज की। टॉस जीतने के बाद वेस्टइंडीज ने दक्षिण अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया जिसके बाद मेहमान टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 160 रन ही बना सकी। वेस्टइंडीज ने इसके जवाब में लुईस की 35 गेंद में 71 रन की पारी की बदौलत 15 ओवर में ही दो विकेट पर 161 रन बनाकर एकतरफा जीत दर्ज की। लुईस ने आंद्रे फ्लेचर (30) के साथ पहले विकेट के लिए 85 और क्रिस गेल (नाबाद 32) के साथ दूसरे विकेट के लिए 39 रन की साझेदारी करके वेस्टइंडीज की आसान जीत की नींव रखी। आंद्रे रसेल ने भी 12 गेंद में नाबाद 23 रन बनाए। लुईस ने अपनी पारी में 4 चौके और 7 छक्के लगाए। वेस्टइंडीज की पारी में कुछ 15 छक्के लगे। शनिवार को हुआ यह मुकाबला 2016 टी20 विश्व कप के बाद दोनों टीमों के बीच पहला टी20 मुकाबला था। वेस्टइंडीज ने 2016 टी20 विश्व कप जीता था। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत अच्छी रही। फॉर्म में चल रहे क्विंटन डिकॉक (24 गेंद में 37 रन) और रेसी वान डेर डुसेन (38 गेंद में नाबाद 56) की पारियों की बदौलत टीम 11वें ओवर में दो विकेट पर 95 रन बनाकर अच्छी स्थिति में थी। टीम ने हालांकि इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रही। वेस्टइंडीज की ओर से फाबियान एलेन ने 18 रन देकर दो जबकि ड्वेन ब्रावो ने 30 रन देकर दो विकेट चटकाए।

इंग्लैंड टीम के लिए भारतीय टीम को हराना कठिन : वॉन

लंदन ।

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कहा है कि मेजबान टीम के लिए भारत के साथ होने वाली सीरीज आसान नहीं रहेगी। वॉन के अनुसार बल्लेबाजी सहित कुछ और क्षेत्रों में मेजबानों को सुधार करना होगा और अगर वे ऐसा नहीं कर पाये तो भारतीय टीम को हराना संभव नहीं होगा। वॉन ने कहा कि विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में हार का मतलब यह नहीं है कि भारतीय टीम कमजोर है। इससे पहले इंग्लैंड को भी न्यूजीलैंड के हाथों टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर मेजबान इंग्लैंड को काम करने की जरूरत है। वॉन के अनुसार इंग्लैड की कमजोर बल्लेबाजी के साथ साथ कुछ और मुद्दे हैं, जो उसे हल करने होंगे। वॉन ने कहा कि आप न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में लॉर्ड्स में कोई स्पिनर नहीं खेला, बिल्कुल ठीक इसी तरह एजबेस्टन में कोई स्पिनर नहीं खेला और मेजबानों की बल्लेबाजी भी कमजोर साबित हुई थी। इससे पहले इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर ने भी कहा था कि भारतीय टीम इस बार टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को 5-0 से हराएगी। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड की बल्लेबाजी उतनी मजबूत नहीं है, जितनी पहले हुआ करती थी। वॉन ने कहा कि भले ही बेन स्टोक्स और बटलर की वापसी हुई है लेकिन जैसी भारतीय गेंदबाजी है उससे इंग्लैंड के बल्लेबाजी क्रम में गहराई की कमी नजर आ रही है। इसके अलावा उनकी टीम को इस सीरीज में जोफा आर्चर के बिना ही खेलना होगा। आर्चर कोहनी की सर्जरी के बाद अभी तक फिट नहीं हो पाये हैं।

भारतीय महिला रिकर्व टीम ने विश्व कप के तीसरे चरण में जीता स्वर्ण पदक

पेरिस।

दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कोमोलिका बारी की भारतीय महिला रिकर्व टीम ने विश्व कप के तीसरे चरण में मेक्सिको पर आसान जीत से स्वर्ण पदक अपने नाम किया। टीम पिछले हफ्ते ओलंपिक क्वालीफाई करने से चूक गई थी और इस स्वर्ण पदक से उसने इस निराशा को कम करने की कोशिश की। दुनिया की तीसरे नंबर की तीरंदाज दीपिका, अंकिता और कोमोलिका की तिकड़ी ने विश्व कप के पहले चरण के फाइनल में भी मेक्सिको को हराकर पहला स्थान हासिल किया था। उसने इस तीसरे चरण में भी मेक्सिको को 5-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता और इस दौरान एक भी सेट नहीं गंवाया। इस साल यह विश्व कप में उनका लगातार दूसरा और कुल मिलाकर छठा (शंघाई 2011, मेडेलिन 2013, रोक्लॉ 2013, रोक्लॉ 2014, ग्वाटेमाला सिटी 2021) स्वर्ण पदक है। हर बार टीम में दीपिका शामिल थी। भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार रहा जिसमें पहले सेट में स्कोर 57-57 था। लेकिन दूसरे सेट में भारतीय टीम ने मेक्सिको की टीम पर दबाव बनाया जिसमें लंदन 2012 की रजत पदक विजेता ऐडा रोमन, एलेजांद्रा वालेंसिया और अन्ना वाज्केज शामिल थीं। दूसरे सेट में मेक्सिको की टीम 52 अंक जुटाकर तीन अंक से पिछड़ गई। भारतीय टीम 3-1 से आगे थी और उसने तीसरे सेट में भी अच्छे निशाने लगाते हुए 55 अंक जुटाये लेकिन मेक्सिको की टीम बराबरी नहीं कर सकी और एक अंक से तीसरा सेट गंवा बैठी। इस तरह उसे इस साल लगातार दूसरी हार झेलनी पड़ी। इससे पहले शनिवार को अभिषेक वर्मा ने कम्पाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था।

संक्षिप्त समाचार

टेनिस : केरबर ने जीता होम्बर्ग ओपन खिताब

फ्रैंकफर्ट। दुनिया की पूर्व नंबर-1 जर्मनी की एंजेलिक केरबर ने बैड होम्बर्ग ओपन खिताब के पहले संस्करण का खिताब जीत लिया है। फाइनल में केरबर ने दुनिया की 76वें नंबर की कतेरीना सिनियाकोवा को 6-3, 6-2 से हराया। इसके साथ केरबर ने अपना 13वां डब्ल्यूटीए करियर एकल खिताब जीता। 2018 विंबलडन में अपने तीन ग्रैंड स्लैम खिताबों में से तीसरा जीतने के के बाद से यह दुनिया की 26 वें नंबर की खिलाड़ी का पहला खिताब मिला है। दो साल में अपने पहले फाइनल में, केर्बर कमांडिंग फॉर्म में थी क्योंकि उसने 1 घंटे 25 मिनट में गैर-वरीय चेक पर जीत हासिल की। 2015 और 2016 में स्टटगार्ट में बैक-टू-बैक खिताब के बाद, यह तीसरी बार घरेलू धरती पर ट्रॉफी ले रहा है। उसे फाइनल में पहुंचने के लिए शुक्रवार को दो वापसी जीत के माध्यम से लड़ना पड़ा, जिसमें सेमीफाइनल में तीसरे सेट के टाईब्रेक के माध्यम से चेक गणराज्य की शीर्ष वरीयता प्राप्त पेट्रा क्वितोवा पर जीत शामिल थी। अब केरबर विंबलडन में खेलेंगी, जहां उनके पास 31-11 करियर जीत-हार का रिकॉर्ड है, जिसमें 2018 का खिताब, 2016 का फाइनल और 2012 में सेमीफाइनल शामिल है।

इटली ने सबसे लंबे समय तक अपने खिलाफ गोल नहीं होने का रिकॉर्ड बनाया और फिर गोल खाया

लंदन । इटली ने 19 घंटे तक शानदार रक्षात्मक खेल की बदौलत अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे लंबे समय तक अपने खिलाफ गोल नहीं होने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा लेकिन इसके सिर्फ 25 मिनट बाद उसके खिलाफ गोल हो गया। इटली के गोलकीपर जियानलुइगी डोनारुमा रिकॉर्ड 1168 मिनट के दौरान अधिकांश समय मैदान पर रहे जिसमें यूरो 2020 के ग्रुप चरण के तीन मुकाबले भी शामिल हैं जिनमें उनके खिलाफ कोई गोल नहीं हुआ। शनिवार को प्री क्वार्टर फाइनल में आस्ट्रिया ने वेम्बले स्टेडियम में इटली के खिलाफ 1-2 की हार के दौरान अंततः टीम के खिलाफ गोल किया। अतिरिक्त समय तक खिंचे मुकाबले में आस्ट्रिया ने प्रभावित किया। टीम की ओर से सासा क्लादजिक ने 114वें मिनट में गोल दागा। सबसे अधिक समय तक गोल नहीं होने देने का पिछला रिकॉर्ड भी इटली ने 1972 और 1974 के बीच बनाया था। तब डिनो जोफ टीम के गोलकीपर थे। यह रिकॉर्ड 1,143 मिनट का था और इस दौरान हर समय जोफ मैदान पर थे। मौजूदा रिकॉर्ड के दौरान डोनारुमा 987 मिनट जबकि सल्वाटोर सिरिगु 91, एलेसियो क्रेगनो 63 और एलेक्स मेरेट 27 मिनट मैदान पर रहे।

शेफाली सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली बनीं सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर

ब्रिस्टल ।

सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा रविवार को यहां इंग्लैंड के खिलाफ पहले महिला एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में उतरते ही सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बनीं। डेब्यू कर रही शेफाली ने कैथरीन ब्रंट की गेंद पर पवेलियन लौटने से पहले 14 गेंद में 15 रन बनाए। हरियाणा की शेफाली ने 17 साल 150 दिन की उम्र में सभी प्रारूपों में डेब्यू किया। वह डेब्यू करने वाले सबसे युवा क्रिकेटरों की सर्वकालिक सूची में पांचवें स्थान पर हैं जिसमें अफगानिस्तान के मुजीब उर रहमान शीर्ष पर हैं। मुजीब ने 17 साल और 78 दिन की उम्र में खेल के सभी प्रारूपों में डेब्यू कर लिया था। इसके बाद इंग्लैंड की सारा टेलर (17 साल और 86 दिन), आस्ट्रेलिया की एलिस पैरी (17 साल और 104 दिन) और पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर (17 साल और 108 दिन) का नंबर आता है। शेफाली ने इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में डेब्यू करते हुए पिछले हफ्ते 96 और 63 रन की पारियां खेली थी। वह महिला टेस्ट में डेब्यू करते हुए दो अर्धशतक जड़ने वाली सबसे युवा बल्लेबाज बनीं थी। सितंबर 2019 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू के बाद शेफाली ने अब तक 22 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में तीन अर्धशतक की मदद से 617 रन बनाए हैं।

श्रीलंका में सभी युवाओं को मौका देने की बात सोचना वास्तविक नहीं होगा : द्रविड़

मुंबई,

श्रीलंका दौरे के लिये भारतीय टीम के मुख्य कोच नियुक्त किये गये राहुल द्रविड़ ने रविवार को कहा कि ऐसा संभव नहीं है कि सीमित ओवरों की श्रृंखला के लिये चुने गये सभी युवा खिलाड़ियों को मैच में खेलने का मौका मिल जायेगा। युवा खिलाड़ी इस साल होने वाले टी20 विश्व कप के लिये अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को प्रभावित करना चाहते हैं और द्रविड़ इस श्रृंखला में कोच की भूमिका में वापसी कर रहे हैं जिनका मानना है कि यह उम्मीद करना कि सभी को इस छोटे से दौरे में मौका मिल जाये, संभव नहीं है। शिखर धवन की कप्तानी में कम अनुभवी टीम श्रीलंका का दौरा करेगी जिसमें छह ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख द्रविड़ ने टीम की रवानगी से पूर्व प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ''मुझे लगता है कि इस संक्षिप्त दौरे पर हमसे यह उम्मीद करना शायद अवास्तविक होगा कि हर किसी को मौका दिया जाये जिसमें तीन टी20 मैच और तीन वनडे हैं। और चयनकर्ता भी वहां होंगे। '' इस साल के विश्व कप के लिये टी20 टीम में जगह बनाने के लिये इन खिलाड़ियों में ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव और संजू सैमसन की तिकड़ी शामिल है। श्रीलंका के खिलाफ श्रृंखला 13 जुलाई से वनडे के साथ शुरू होगी जिसके बाद 21 जुलाई से टी20 मैच खेले जायेंगे। विश्व कप को पहले भारत में होना था लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसका आयोजन अक्टूबर में संयुक्त अरब अमीरात में होगा। श्रीलंका में एक दिवसीय मैचों की तुलना में तीन टी20 ज्यादा अहमियत रखेंगे क्योंकि विश्व कप से पहले यह भारत के अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच होंगे। पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा, ''इस टीम में काफी खिलाड़ी हैं जो आगामी विश्व के लिये टीम में अपना स्थान पक्का करना चाहते हैं और कुछ जगह बनाना चाहते हैं लेकिन मुझे लगता है कि टीम में हर किसी का मुख्य लक्ष्य श्रृंखला जीतने की कोशिश करना है। '' उन्होंने कहा, ''मुख्य उद्देश्य श्रृंखला जीतना है और उम्मीद करते हैं कि खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिये मौका मिलेगा। विश्व कप से पहले सिर्फ तीन टी20 मैच ही हैं। '' उन्होंने कहा, ''मुझे पूरा भरोसा है कि चयनकर्ताओं और प्रबंधन को अब तक अंदाजा हो गया होगा कि वे किस तरह की टीम चाहते हैं। ''

आई-लीग दिसंबर के मध्य में कोलकाता में शुरू होगी: एआईएफएफ

नई दिल्ली। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) इस सीजन में हीरो आई-लीग का आयोजन कोलकाता में करने की योजना बना रहा है। आई-लीग के सीईओ सुनंदो धर ने शनिवार को वर्चुअली आयोजित एआईएफएफ लीग समिति की बैठक के दौरान कहा कि इस सीजन में आई-लीग 13-टीम का होगा, जिसमें पिछले संस्करण के 80 से 114 तक के मैचों की संख्या होगी। पैनल ने यह भी फैसला किया कि मौजूदा स्थिति की परवाह किए बिना आई-लीग 2021/22 पर निर्वासन नियम लागू किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय महिला लीग के 2020/21 संस्करण पर निर्णय, जिसे महामारी की दूसरी लहर के कारण स्थगित कर दिया गया था, लीग के अंतिम दौर के मेजबान ओडिशा स्पोर्ट्स के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के बाद लिया जाएगा।

श्रीलंका सीरीज हम सभी के लिए अपना कौशल दिखाने का शानदार मौका : धवन

मुंबई ।

श्रीलंका के सीमित ओवरों के दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान चुने गए शिखर धवन ने आगामी श्रृंखला को चुनौतीपूर्ण करार देते हुए रविवार को यहां कहा कि इससे दूसरी श्रेणी के खिलाड़ियों को अपना कौशल दिखाने और मुख्य टीम में जगह बनाने का मौका मिलेगा। धवन ने मुख्य कोच राहुल द्रविड़ की उपस्थिति में टीम की रवानगी से पहले वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'यह बहुत अच्छी टीम है। हमारी टीम में सकारात्मकता है, विश्वास है और हर किसी को अच्छा प्रदर्शन करने का भरोसा है। खिलाड़ी बेहद उत्साहित हैं।' उन्होंने कहा, 'यह नई चुनौती है लेकिन इसके साथ ही यह हम सभी के लिये अपना कौशल दिखाने का शानदार मौका है। हर कोई इसका इंतजार कर रहा है।' धवन ने कहा, 'हमारे पृथकवास के 13-14 दिन गुजर चुके हैं और खिलाड़ी मैदान पर उतरने के लिए बेताब हैं। हमारे पास तैयारी के लिये 10-12 दिन हैं।' नियमित कप्तान विराट कोहली और मुख्य टीम के इंग्लैंड दौरे पर होने के कारण धवन श्रीलंका के खिलाफ अगले महीने भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे। भुवनेश्वर कुमार टीम के उप कप्तान हैं। भारत को श्रीलंका से तीन एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों और इतने ही टी20 मैचों में खेलना है। दौरे की शुरुआत 13 जुलाई को और समापन 25 जुलाई होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने दौरे के लिए 20 सदस्यीय टीम का चयन किया है जिसमें हार्दिक पंड्या तथा स्पिनर कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल भी शामिल हैं। युवा बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल और पृथ्वी सॉव पर भी सभी की निगाह टिकी रहेगी। टीम में इशान किशन और संजू सैमसन के रूप में दो विकेटकीपर भी है। धवन ने टीम संयोजन के बारे में कहा, 'खिलाड़ी तैयार हैं और वे इन मैचों में खेलने के लिए बेताब है। इन खिलाड़ियों ने आईपीएल और अन्य टूर्नामेंटों में पहले ही खुद को साबित किया है।' पहली बार भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे बायें हाथ के इस बल्लेबाज ने कहा, 'टीम युवा और अनुभव का अच्छा मिश्रण है।'

आकाश चोपड़ा ने पुजारा, बुमराह और जडेजा को दिये सबसे कम अंक

नई दिल्ली । पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के फाइनल में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा के लचर प्रदर्शन पर सवाल उठाये हैं। आकाश ने सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को 10 में से छह अंक दिए। चोपड़ा ने कहा कि रोहित ने दोनों पारियों में नई गेंद का अच्छे से सामना किया, जबकि विदेशी पिचों पर यह सबसे मुश्किल काम था। रोहित ने जो किया है उसे कम नहीं आंका जा सकता। वहीं शुभमन गिल ने पहली पारी में रोहित शर्मा की सहायत की पर दूसरी पारी में वह जल्दी पेवेलियन लौट गए। चोपड़ा ने शुभमन को 10 में से चार अंक दिए हैं। चोपड़ा ने कहा कि पुजारा स्लिप में एक कैच छोड़ा, हालांकि इससे मैच पर ज्यादा फर्क नहीं आता। साथ ही कहा कि भारतीय टीम को दोनों पारियों में पुजारा से बड़े स्कोर की उम्मीद थी पर उन्होंने निराश किया। उन्होंने पुजारा को 10 में केवल 2 अंक ही दिये। कप्तान विराट कोहली को 10 में से 5 अंक मिले। चोपड़ा ने कहा कि उनकी पहली पारी अच्छी थी पर दूसरी पारी में उनसे अधिक की उम्मीद की जा रही थी। कोहली को कीवी कप्तान तुलना केन विलियमसन की तरह दोनो ही पारियों में रन बनाने थे। चोपड़ा ने अजिंक्य रहाणे को भी केवल 5 अंक ही दिये। उन्होंने कहा कि रहाणे ने पहली पारी में 49 रन बनाए। वह खराब शॉट खेलकर आउट हुए। आप कह सकते हैं कि वह दूसरी पारी में बदकिस्मत थे पर वे कभी भी बल्लेबाजी में सहज नजर नहीं आये। रवींद्र जडेजा को 10 में से तीन अंक मिले। चोपड़ा ने कहा कि आप सातवें नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और दोनों पारियों में जडेजा की बल्लेबाजी से ज्यादा उम्मीदें थीं। आपने गेंदबाजी करते हुए एक विकेट लिया, दूसरी पारी में भी विकेटों की उम्मीद ज्यादा थी जो पूरी नहीं हुई। वहीं आर अश्विन को चोपड़ा ने छह अंक दिया।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

ऑक्सीजन देने वाले वृक्ष के आध्यात्मिक रहस्य

हर धर्म में पेड़, पौधे और वृक्षों का बहुत महत्व है, परंतु इसको कोई महत्व नहीं देता है। जिस देजी से वृक्ष कटते जा रहे हैं उससे धरती का पर्यावरण ही नहीं बदल रहा है बल्कि जीवन में संकट में हो चला है। धरती पर ऑक्सीजन का निर्माण करने में वृक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वृक्ष नहीं होंगे तो एक दिन वायु भी नहीं होगी और वायु नहीं होगी तो फिर मानव भी नहीं होगा। आओ जानते हैं वृक्ष के 20 रहस्य।

- शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति एक पीपल, एक नीम, दस इमली, तीन कैथ, तीन बेल, तीन आंवला और पांच आम के वृक्ष लगाता है, वह पुण्यात्मा होता है और कभी नरक के दर्शन नहीं करता। इसी तरह धर्म शास्त्रों में सभी तरह से वृक्ष सहित प्रकृति के सभी तत्वों के महत्व की विवेचना की गई है।
- भारतीय धर्म मानता हैं कि प्रकृति ही ईश्वर की पहली प्रतिनिधि है। प्रकृति के सारे तत्व ईश्वर के होने की सूचना देते हैं। इसीलिए प्रकृति को देवता, भगवान और पितृ माना गया है। यहां प्रत्येक देवी और देवता से एक वृक्ष, एक पशु या एक पक्षी जुड़ा हुआ है। यहां तक की ग्रह और नक्षत्र भी जुड़े हुए हैं। धर्म मानता है कि दूरस्थ स्थिति ध्रुव तारा भी हमारे जीवन को संचालित कर रहा है। फिर हिमालय के ग्लेशियर और चंद्रमा के तो कहने ही क्या। संपूर्ण ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक कड़ी टूटी तो सबकुछ बिखर जाएगा। यह ब्रह्मांड उल्टे वृक्ष की भांति है।
- धर्मानुसार पांच तरह के यज्ञ होते हैं जिनमें से दो यज्ञ- देवयज्ञ और वैश्वदेवयज्ञ प्रकृति को समर्पित है। दोनों ही तरह के यज्ञों का वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व है। देवयज्ञ से जलवायु और पर्यावरण में सुधार होता है तो वैश्वदेवयज्ञ प्रकृति और प्राणियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का तरीका है। सभी प्राणियों तथा वृक्षों के प्रति करुणा और कर्त्तव्य समझना उन्हें अन्न-जल देना ही भूतयज्ञ या वैश्वदेव यज्ञ कहलाता है।
- हिन्दू धर्मानुसार वृक्ष में भी आत्मा होती है। वृक्ष संवेदनशील होते हैं और उनके शक्तिशाली भावों के माध्यम से आपका जीवन बदल सकता है। प्रत्येक वृक्ष का गहराई से विश्लेषण करके हमारे ऋषियों ने यह जाना की पीपल और वट वृक्ष सभी वृक्षों में कुछ खास और अलग है। इनके धरती पर होने से ही धरती के पर्यावरण की रक्षा होती है। यही सब जानकर ही उन्होंने उक्त वृक्षों के संवरक्षण और इससे मनुष्य के द्वारा लाभ प्राप्ति के हेतु कुछ विधान बनाए गए उन्ही में से दो है पूजा और परिक्रमा।
- स्कन्द पुराण में वर्णित पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का वास है। पीपल की छाया में ऑक्सीजन से भरपूर आरोग्यवर्धक वातावरण निर्मित होता है। इस वातावरण से वात, पित्त और कफ का शमन-नियमन होता है तथा तीनों स्थितियों का संतुलन भी बना रहता है। इससे मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। पीपल की पूजा का प्रचलन प्राचीन काल से ही रहा है। इससे मानसिक शांति भी प्राप्त होती है।
- अथर्ववेद के उपवेद आयुर्वेद में पीपल के औषधीय गुणों का अनेक असाध्य रोगों में उपयोग वर्णित है। औषधीय गुणों के कारण पीपल के वृक्ष को 'कल्पवृक्ष' की संज्ञा दी गई है। पीपल के वृक्ष में जड़ से लेकर पत्तियों तक तैंतीस कोटि देवताओं का वास होता है और इसलिए पीपल का वृक्ष प्रातः पूजनीय माना गया है। उक्त वृक्ष में जल अर्पण करने से रोग और शोक मिट जाते हैं। पीपल की पूजा का प्रचलन प्राचीन काल से ही रहा है। इसके कई पुरातात्विक प्रमाण भी है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, 'हे पार्थ वृक्षों में मैं पीपल हूं।'
अश्वत्थोपनयन व्रत के संदर्भ में महर्षि शौनक कहते हैं कि मंगल मुहूर्त में पीपल वृक्ष की नित्य तीन बार परिक्रमा करने और जल चढ़ाने पर दरिद्रता, दुःख और दुर्भाग्य का विनाश होता है। पीपल के दर्शन-पूजन से दीर्घायु तथा समृद्धि प्राप्त होती है। अश्वत्थ व्रत अनुष्ठान से कन्या अखण्ड सौभाग्य पाती है। सड़क के किनारे पीपल का वृक्ष लगाने, तथा उसका पालन करने वाला देवलोक प्राप्त करता है। पीपल के वृक्षों का रोपण करने वाला इस लोक में तो कीर्ति प्राप्त करता है, मृत्युपरांत भी मोक्ष को प्राप्त होता है। इसमें संदेह नहीं है।
- बरगद को वटवृक्ष कहा जाता है। हिंदू धर्म में वट सावत्री नामक एक त्योहार पूरी तरह से वट को ही समर्पित है। हिंदू धर्मानुसार चार वटवृक्षों का महत्व अधिक है। अक्षयवट, पंचवट, वंशीवट, गयावट और सिद्धवट के बारे में कहा जाता है कि इनकी प्राचीनता के बारे में कोई नहीं जानता। संसार में उक्त चार वटों को पवित्र वट की श्रेणी में रखा गया है। प्रयाग में अक्षयवट, नासिक में पंचवट, वृंदावन में वंशीवट, गया में गयावट और उज्जैन में पवित्र सिद्धवट है।
- **आम है खास** : हिंदू धर्म में जब भी कोई माँगलिक कार्य होते हैं तो घर या पूजा स्थल के द्वार व दीवारों पर आम के पत्तों की लड़ लगाकर मांगलिक उत्सव के माहौल को धार्मिक और वातावरण को शुद्ध किया जाता है। अक्सर धार्मिक पांडाल और मंडपों में सजावट के लिए आम के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। 5 या अधिक आम के वृक्षों का रोपण पालन करने वाला अनेक दुर्लभ यज्ञों के फल को प्राप्त कर सकता है।
- **भविष्यवक्ता शमी** : विक्रमादित्य के समय में सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर ने अपने बृहतसंहिता' नामक ग्रंथ के 'कुसुमलता' नाम के अध्याय में वनस्पति शास्त्र और कृषि उपज के संदर्भ में जो जानकारी प्रदान की है उसमें शमीवृक्ष अर्थात खिजड़े का उल्लेख मिलता है। वराहमिहिर के अनुसार जिस साल शमीवृक्ष ज्यादा फूलता-फलता है उस साल सूखे की स्थिति का निर्माण होता है। विजयादशमी के दिन इसकी पूजा करने का एक तात्पर्य यह भी है कि यह वृक्ष आने वाली कृषि विपत्ती का पहले से संकेत दे देता है जिससे किसान पहले से भी ज्यादा पुरुषार्थ करके आनेवाली विपत्ती से निजात पा सकता है।
- जो मनुष्य अपने घर में फलदार पेड़, पौधे आदि लगाता है और उसकी भली भांति देखभाल करता है, उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है।
- जो मनुष्य 5 वट वृक्षों का रोपण और उसका पालन किसी चौराहे या मार्ग में करता है तो, उसकी सात पीढ़ियां तर जाती है। जो मनुष्य नीम के वृक्ष जितने अधिक लगाता है उतनी अधिक उसकी पीढ़ियां तर जाती है.
- वृक्षों के बाग या वाटिका लगाने वाला प्रसिद्धि प्राप्त करता है।
- जो भी व्यक्ति बिल्व वृक्ष का रोपण शिव मंदिर में करता है वह अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाता है।
- घर में तुलसी, आंवला, निर्गुण्डी, अशोक, आदि के वृक्ष शुभ फलदायी होते हैं। शीशम के 11 वृक्ष को सड़क पर लगाने से यह लोक और परलोक दोनों ही संवर जाते हैं।
- कनक चम्पा के 2 वृक्ष लगाने वाले का सर्वार्थ कल्याण हो जाता है।
- 5 या अधिक महुआ के वृक्षों का रोपण और पालन करने वाला धन प्राप्त करता है। तथा उसे अनुरूप यज्ञों का फल भी प्राप्त होने लगता है।
- जो भी मनुष्य सड़क के किनारे 2 या 2 से अधिक मौलश्री के वृक्षों का रोपण एवं पालन करता है। वह एक सौ यज्ञों को करने का पुण्य प्राप्त करता है।
- जो भी मनुष्य 5 या अधिक अशोक वृक्ष का रोपण और पालन करता है, उसके घर परिवार में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। उसके यहां अचानक कोई बड़ी मुसीबत खड़ी नहीं होती तथा उसे आगामी जन्म में पुण्यात्मा होने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
- जो मनुष्य 5 पलास के वृक्षों का रोपण और पालन करते हैं। उसे 10 गौवों के दान के समतुल्य पुण्य लाभ मिलता है। पलास के वृक्षों को सड़क के किनारे अथवा किसी बड़े क्षेत्र में रोपना चाहिए। इसका रोपण घर में नहीं करना चाहिए।
- जो भी मनुष्य 2 या अधिक हारसिंगार (पारिजात) के पौधों का रोपण श्री हनुमानजी के मंदिर में अथवा नदी के किनारे या किसी भी सामाजिक स्थल पर करता है तो उसे एक लक्ष्य तोला स्वर्णदान के समतुल्य पुण्य प्राप्त होता है तथा उसे जीवन भर श्री हनुमानजी की कृपा मिलती रहती है।
- जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन, प्रदोष वाले दिन, शिवरात्री को, श्रावणमास में किसी भी दिन अथवा शिवयोग वाले दिन 5 या अधिक बिल्व वृक्षों का रोपण और उसका नियमित पालन भी करता है तो उसे शिवलोक प्राप्त होता है। यदि इन वृक्षों को कोई भी मनुष्य शिव मंदिर में या मंदिर के समीप रोपण करता है तो निश्चय ही वह कोटि कोटि पुण्य का भागीदार तो होता ही है और उसे व उसके परिवार पर भगवान शिव की असीम अनुकम्पा भी प्राप्त होती है।

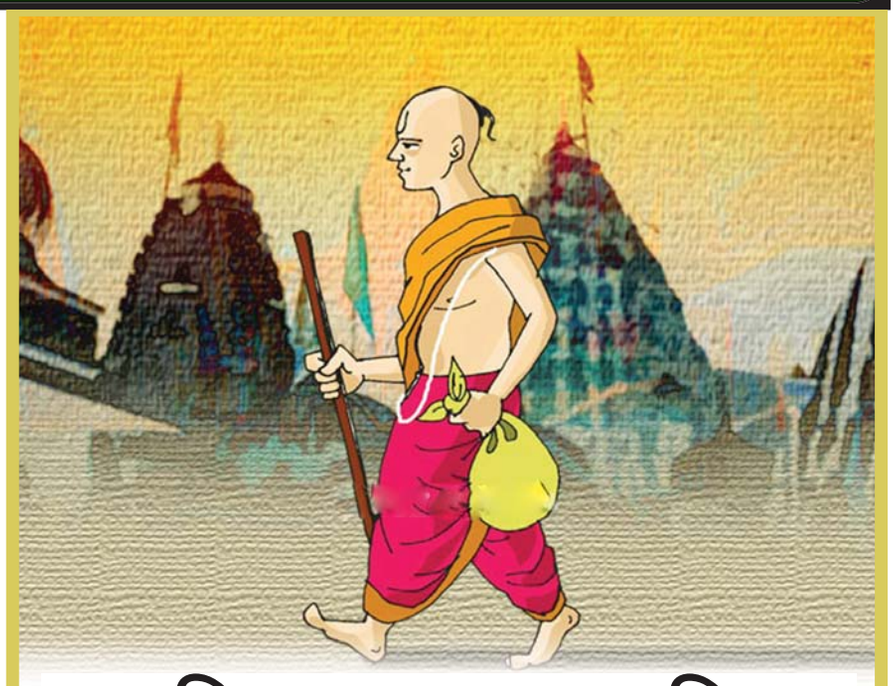

परिक्रमा या प्रदक्षिणा के 10 प्रकार

सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और सभी ग्रहों को साथ लेकर यह सूर्य महासूर्य की परिक्रमा कर रहा है। संपूर्ण ब्रह्माण में चक्र और परिक्रमा का बड़ा महत्व है। भारतीय धर्मों (हिन्दू, जैन, बौद्ध आदि) में पवित्र स्थलों के चारो ओर श्रद्धाभाव से चलना 'परिक्रमा' या 'प्रदक्षिणा' कहलाता है। आओ जानते हैं कि किन किन की परिक्रमा की जाती है या कितने प्रकार की परिक्रमा की जाती है। ये हैं प्रमुख 10 परिक्रमाएं -

देवमंदिर परिक्रमा

जैसे देव मंदिर में जगन्नाथ पुरी परिक्रमा, रामेश्वरम, तिरुवन्नमल, तिरुवनन्तपुरम, शक्तिपीठ, ज्योतिर्लिंग आदि।

देव मूर्ति परिक्रमा

देवमूर्ति में शिव, दुर्गा, गणेश, विष्णु, हनुमान, कार्तिकेय आदि देवमूर्तियों की परिक्रमा करना।

नदी परिक्रमा

जैसे नर्मदा, सिंधु, सरस्वती, गंगा, यमुना, सरयु, क्षिप्रा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी परिक्रमा आदि।

पर्वत परिक्रमा

जैसे गोवर्धन परिक्रमा, गिरनार, कामदगिरि, मेरू पर्वत, हिमालय, नीलगिरी, तिरुमलै परिक्रमा आदि।

वृक्ष परिक्रमा

जैसे पीपल और बरगद की परिक्रमा करना।

तीर्थ परिक्रमा

जैसे चौरासी कोस परिक्रमा, अयोध्या, उज्जैन या प्रयाग पंचकोशी यात्रा, राजिम परिक्रमा, सप्तपुरी आदि।

चार धाम परिक्रमा

जैसे छोटा चार धाम (केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री) परिक्रमा या बड़ा चार धाम (बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथ और रामेश्वरम) यात्रा।

भरत खण्ड परिक्रमा

अर्थात संपूर्ण भारत की परिक्रमा करना। परिवाजक संत और साधु ये यात्राएं करते हैं। इस यात्रा के पहले क्रम में सिंधु की यात्रा, दूसरे में गंगा की यात्रा, तीसरे में ब्रह्मपुत्र की यात्रा, चौथे में नर्मदा, पांचवें में महानदी, छठे में गोदावरी, सातवें में कावेरी, आठवें में कृष्णा और अंत में कन्याकुमारी में इस यात्रा का अंत होता है। हालांकि प्रत्येक साधु समाज में इस यात्रा का अलग-अलग विधान और नियम है।

विवाह परिक्रमा

मनु स्मृति में विवाह के समक्ष वधू को अग्नि के चारों ओर तीन बार प्रदक्षिणा करने का विधान बतलाया गया है जबकि दोनों मिलकर 7 बार प्रदक्षिणा करते हैं तो विवाह संपन्न माना जाता है।

माता पिता की परिक्रमा

भगवान गणेशजी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की थी जिससे पता चलता है कि इस परिक्रमा का क्या महत्व है।

शव परिक्रमा

जब कोई किसी का अपना देह छोड़ देता है कि उसकी देह की परिक्रमा की जाती है। दाह संस्कार करते वक्त और करने के बाद मटकी से जल अर्पित करते वक्त भी परिक्रमा की जाती है।

धरती की परिक्रमा

एक बार देवताओं के बीच में धरती परिक्रमा की प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें जीते तो भगवान कार्तिकेय थे परंतु गणेशजी ने माता पिता की परिक्रमा करके यह प्रतियोगिता जीत ली थी।

ब्रह्मांड की परिक्रमा

यह परिक्रमा नारद जी करते रहते हैं।

किस देव की कितनी बार परिक्रमा?

- भगवान शिव की आधी परिक्रमा की जाती है।
- माता दुर्गा की एक परिक्रमा की जाती है।
- हनुमानजी और गणेशजी की तीन परिक्रमा की जाती है।
- भगवान विष्णु की चार परिक्रमा की जाती है।
- सूर्यदेव की चार परिक्रमा की जाती है।
- पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमाएं करना चाहिए।
- जिन देवताओं की प्रदक्षिणा का विधान नहीं प्राप्त होता है, उनकी तीन प्रदक्षिणा की जा सकती है।

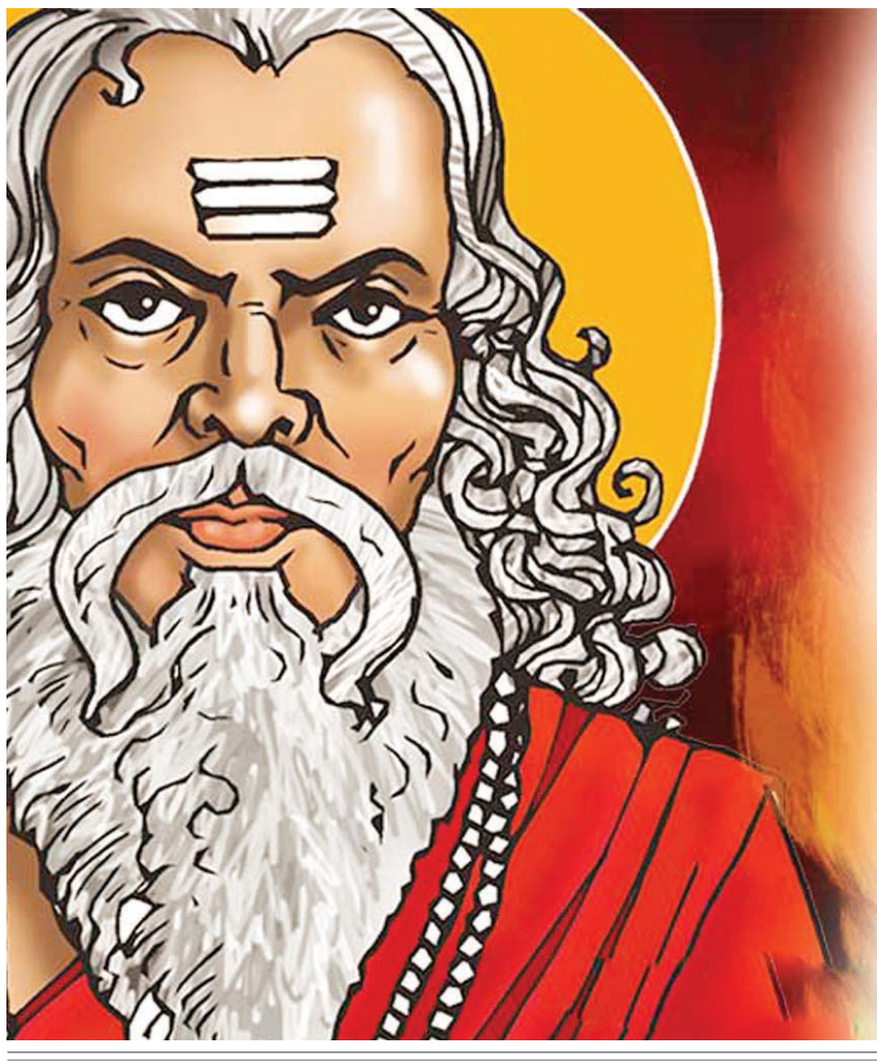

ब्रह्मा के पुत्र क्रतु ऋषि के थे 60 हजार पुत्र

पुराणों अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र- मन से मारिचि, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरस, कान से पुलस्त्य, नाभि से पुलह, हाथ से कृतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगुष्ठ से दक्ष, छाया से कंदर्भ, गोद से नारद, इच्छा से सनक, सनन्दन, सनातन, सनतकुमार, शरीर से स्वायंभुव मनु, ध्यान से चित्रगुप्त आदि। आओ जानते हैं ऋषि अंगिरा के बारे मं संक्षिप्त में जानकारी।

ब्रह्मा के पुत्र कृतु ऋषि :

- कृतु या क्रतु का जन्म ब्रह्माजी के हाथ से हुआ था। क्रतु 16 प्रजापतियों में से एक हैं। इनकी गणना सप्तर्षियों में की जाती है।
- ब्रह्मा की आज्ञा से उन्होंने दक्ष प्रजापति और क्रिया की पुत्री सन्नति से विवाह किया था। कहते हैं कि क्रतु और सन्नति से 'बालिखिल्य' नाम के 60 हजार पुत्र हुए। इन बालखिल्यों का आकार अंगूठे के बराबर माना जाता है। यह सभी पुत्र भगवान सूर्य के उपासक थे। सूर्य के रथ के आगे अपना मुख सूर्य की ओर किये हुए बालखिल्य चलते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। इन ब्रह्मर्षियों की तपस्या शक्ति सूर्यदेव को प्राप्त होती रहती है।
- पुराणों अनुसार एक बार महर्षि मरीचि के पुत्र महर्षि कश्यप एक यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने अपने तात महर्षि क्रतु से निवेदन किया कि वे उस यज्ञ के लिए ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करें। अपने भतीजे के निवेदन पर महर्षि क्रतु अपने 60 हजार पुत्रों के साथ महर्षि कश्यप के यज्ञ में पधारे। उसी यज्ञ में देवराज इंद्र और महर्षि क्रतु के पुत्र बालखिल्यों में विवाद हो चला तब अपने पिता और महर्षि कश्यप द्वारा बीच-बचाव करने पर बालखिल्यों ने ही पक्षीराज गरुड़ को महर्षि कश्यप को पुत्र रूप में प्रदान किया था।
- पुराणों में महर्षि क्रतु की दो बहनों- पुण्य एवं सत्यवती का भी वर्णन मिलता है। महर्षि क्रतु और सन्नति की एक पुत्री का नाम भी पुण्य था। इसके साथ ही पर्वासा नाम की एक पुत्रवधु का भी वर्णन मिलता है।
- सर्वप्रथम वेद एक रूप में ही ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न किए गए थे। बाद में महर्षि क्रतु ने ही वेदों के चार भाग करने में उनकी सहायता की थी। आगे चलकर वराहकल्प में क्रतु ऋषि ही महाभारत काल में वेद व्यास ऋषि हुए।
- मनु के पुत्र उत्तानपाद और उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव से महर्षि क्रतु अत्यंत प्रेम करते थे। जब अपने पिता से उपेक्षित होकर ध्रुव ने परमलोक की प्राप्ति करने की सोची तो सबसे पहे वो महर्षि क्रतु के पास गया। क्रतु ने ध्रुव को भगवान विष्णु की तपस्या करने की सलाह दी। बाद में देवर्षि नारद द्वारा अनुमोदन करने पर ध्रुव ने विष्णुजी की घोर तपस्या की और उनकी कृपा से परमलोक को प्राप्त हुआ। क्रतु ऋषि नाम का एक तारा है जो ध्रुव की परिक्रमा करने में आज भी लीन है। ध्रुव के प्रति अपने प्रेम के कारण ही महर्षि क्रतु उसके समीप चले गए।
- पुराणों में महर्षि क्रतु को महर्षि अगस्त्य के वातापि भक्षण और समुद्र को पी जाने के कारण उनकी प्रशंसा करते हुए भी बताया गया है। कुछ ग्रंथों में इस बात का वर्णन है कि महर्षि क्रतु ने महर्षि अगस्त्य के पुत्र ईधवाहा को भी गोद लिया था। इसके अलावा महाराज भरत ने महर्षि क्रतु से देवताओं के चरित्र के विषय में प्रश्न किया था। तब महर्षि क्रतु ने उनकी इस शंका का समाधान किया था।
- क्रतु नाम से एक अग्नि का नाम भी है और श्रीकृष्ण और जाम्बवती के कई पुत्रों में से एक का नाम क्रतु था। प्लक्षद्वीप की एक नदी का नाम भी क्रतु है। क्रतु का एक अर्थ 'आषाढ़' भी होता है और वर्ष के इसी मास में अधिकांश यज्ञ करने का प्रावधान शास्त्रों में बताया गया है।
- मैत्रेय संहिता के अनुसार एक बार यज्ञ से प्राप्त पशुओं का देवाताओं ने विभाजन कर दिया और उन्होंने रुद्र को उस विभाजन के हिस्से में शामिल नहीं किया तब रुद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में पूषणा के दन्त, भग के नेत्र और क्रतु के अंडकोषों को नष्ट हो गए। बाद में ब्रह्माजी ने उनकी स्तुति करके उन्हें शांत किया और उन्हें 'पशुपति' की उपाधि दी। फिर रुद्रदेव ने सभी को पहले जैसा कर दिया।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

फ्लोरिडा में इमारत ढहने से 5 लोगों की मौत, 156 लोग लापता

सर्फसाइड (अमेरिका)। दक्षिण फ्लोरिडा में मियामी के निकट शनिवार को 12 मंजिला इमारत के गिरने से पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि 156 लोग लापता हैं। बचावकर्ता जीवित बचे लोगों को मलबे में लगी आग और उसके कारण उठ रहे धुएं के बीच तलाश रहे हैं। मियामी-डाडे की मेयर डेनिला लेविने कावा ने बताया कि मलबे से अब तक पांच लोगों के शव निकाले गए हैं और 156 लोग अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा, ''हमारी शीर्ष प्राथमिकता तलाश और बचाव अभियान तेज करना है, ताकि उन लोगों की जान बचाई जा सके, जिन्हें हम बचा सकते हैं।'' इससे पहले उन्होंने बताया था कि मलबे में लगी आग की लपटें बहुत तेज हैं, जिसके कारण बचाव अभियान में बहुत दिक्कत हो रही है। एक क्रेन ने सर्फसाइड शहर में 30 फुट ढेर से मलबे के टुकड़े हटाए और बचाव दल ने मलबे को हटाने के लिए बड़ी मशीनों, छोटी बाल्टियों, ड्रोन और माइक्रोफोन समेत कई उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने ट्वीट किया कि उन्होंने फ्लोरिडा के गवर्नर रोन डेसांटिस से शुक्रवार को बात की और उन्हें हर संभव मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने इस घटना पर खेद प्रकट दिया। प्राधिकारियों ने घोषणा की कि वे ढही इमारत 'शैम्प्लेन टावर्स साउथ' की तरह 40 साल पुरानी इमारतों की समीक्षा करेंगे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे सुरक्षित हैं या नहीं। डेसांटिस ने बताया कि संघीय आपात प्रबंधन एजेंसी के अधिकारी दुर्घटनास्थल पर स्थानीय एवं राज्य प्राधिकारियों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो इमारत ढही है, उसकी निकटवर्ती इमारतों पर भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि वे भी उतनी ही पुरानी हैं और उनका नक्शा भी एक सा है।

कोरोना रोकथाम के लिए थाईलैंड ने लगाए नए प्रतिबंध

बैंकॉक। थाईलैंड ने राजधानी बैंकॉक और नौ प्रांतों में कड़े प्रतिबंधों की घोषणा की है, क्योंकि मौजूदा उपाय ताजा कोविड मामलों को बढ़ने से रोकने में विफल रहे हैं। थाईलैंड के शाही राजपत्र द्वारा जारी एक दस्तावेज के अनुसार, बैंकॉक और पांच पड़ोसी प्रांतों के साथ-साथ चार दक्षिणी प्रांतों में कम से कम 30 दिनों के लिए रेस्तरां डाइन-इन पर प्रतिबंध सोमवार से लागू होगा। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिबंधों के लिए बैंकॉक में शॉपिंग मॉल और चयनित प्रांतों को रात 9 बजे तक बंद करने की आवश्यकता थी। होटलों और सम्मेलन केंद्रों में 20 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। कोरोनोवायरस के और प्रसार को रोकने के लिए अधिकारी कम से कम 30 दिनों के लिए बैंकॉक और नौ चयनित प्रांतों के अंदर और बाहर सड़क यातायात की निगरानी करेंगे। नए उपाय तब आए जब दक्षिण पूर्व एशियाई देश 120 दिनों में पूरी तरह से टीकाकरण वाले पर्यटकों के लिए फिर से खोलने और फुकेत को अगले सप्ताह एक निर्दिष्ट क्वारंटीन मुक्त पर्यटन स्थल के रूप में लॉन्च करने की योजना बना रहा है। थाईलैंड ने रविवार को 3,995 नए कोविड -19 मामले दर्ज किए, 3,000 से ऊपर नए संक्रमण के लगातार 11वें दिन, और 42 अतिरिक्त मौतें हुईं। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि देश में संक्रमण की संख्या अब 244,447 है, जिसमें मरने वालों की संख्या 1,912 है।

तंजानिया में बागमायो बंदरगाह परियोजना पर फिर शुरू होगा काम: राष्ट्रपति

दार अस सलाम। तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलुहू हसन ने कहा कि बागामोयो बंदरगाह परियोजना को शुरू करने के विषय पर चर्चा जारी है। राष्ट्रपति हसन ने शनिवार को यहां स्टेट हाउस में तंजानिया नेशनल बिजनेस काउंसिल की एक बैठक में बताया कि बगामायो बंदरगाह परियोजना को देश के लाभ के लिए जल्द शुरू किया जाना चाहिए। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा कि सरकार अन्य प्रमुख परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया में है, जिसमें दक्षिणी तंजानिया के मचुचुमा और लिगंगा में कोयला और लौह अयस्क खदान की परियोजनाएं शामिल हैं। तंजानिया प्राइवेट सेक्टर फाउंडेशन (टीपीएसएफ) की अपील का जवाब देते हुए राष्ट्रपति हसन ने बंदरगाह परियोजना को पुनर्जीवित करने की सरकार की मंशा का खुलासा किया। टीपीएसएफ की अध्यक्ष एंजेलिना नगलुला ने कहा कि देश को वैश्विक व्यापार से निपटने में सक्षम बनाने के लिए बागामोयो बंदरगाह की बहुत आवश्यकता है। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि बंदरगाह व्यापार के लिए रणनीतिक महत्व का है। दिवंगत राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली द्वारा इसे स्थगित किए जाने के बाद बागमोयो बंदरगाह परियोजना की प्रगति धीमी हो गई थी और इसके बजाय दार एस सलाम बंदरगाह के विस्तार और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

रूस काला सागर में अमेरिकी विध्वंसक की निगरानी करेगा

मॉस्को। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसका काला सागर बेड़ा अमेरिकी निर्देशित मिसाइल विध्वंसक रॉस पर नजर रख रहा है, जिसने यूक्रेन के साथ एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास के लिए पानी में प्रवेश किया है। अमेरिकी नौसेना के छठे बेड़े ने शनिवार को कहा कि अर्ले बर्क क्लास विध्वंसक अगले सप्ताह से शुरू होने वाले अभ्यास सी ब्रीज 2021 के समुद्री हिस्से में भाग लेने के लिए 31 अन्य जहाजों में शामिल होगा। समाचार एजेंसी ने यूक्रेन में अमेरिकी दूतावास में चार्ज डी अफेयर्स क्रिस्टीना केविन के हवाले से कहा है कि इस साल के अभ्यास में रॉस की भागीदारी यूक्रेन के लिए अमेरिकी समर्थन का एक ठोस प्रदर्शन है और वाशिंगटन और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) द्वारा काला सागर में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए की गई स्थायी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। हालांकि, रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने शनिवार को कहा कि नाटो यूक्रेन अभ्यास का उद्देश्य रूसी सीमाओं के पास अंतहीन अस्थिरता पैदा करना और हथियारों और उपकरणों को यूक्रेन में स्थानांतरित करना है।

भारत से पंगा पाक को पड़ रहा महंगा, आतंकवाद पर एक्शन को लेकर बन रहा भारी दबाव

इस्लामाबाद। (एजेंसी)।

आतंकवाद को लेकर भारत का दबाव पकिस्तान पर भारी पड़ रहा है। भारत द्वारा दिए गए ठोस सबूतों के चलते ही पाकिस्तान एक बार फिर एफएटीएफ की ग्रे सूची से बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो पाया। वहीं, अब उसपर यूएन द्वारा घोषित आतंकियों पर कार्रवाई को लेकर पहले से ज्यादा दबाव बढ़ गया है।

जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान बनावटी कार्रवाई करके खुद को पाक साफ नहीं घोषित कर सकता। क्योंकि अब ज्यादा सख्त तरीके से निगरानी हो रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो छिटपुट देश पाकिस्तान के समर्थन में हैं वे भी आतंकवाद के खिलाफ बने वैश्विक माहौल की वजह से उसका बचाव नहीं कर सकते। चीन भी एससीओ से लेकर ब्रिक्स तक हर जगह भारत की आतंकरोधी रणनीति को स्वीकार करने के लिए बाध्य हुआ है।

सामरिक मामलों के जानकार और विवेकानंद फाउंडेशन के सीनियर फेलो पीके मिश्र का कहना है कि पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर भारत की ब्यूह रचना से बच नहीं सकता। भारतीय एजेंसियों ने पुख्ता होमवर्क करके सबूत एकत्र किए हैं और पहले एशिया पैसिफिक समूह और एफएटीएफ की बैठक में शामिल सदस्य देशों के साथ भी इसे साझा किया है। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से काफी प्रयास किए। पाक विदेश मंत्री ने कहा कि भारत को एफएटीएफ के राजनीतिक उपयोग की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन उसकी बेवजह बयानबाजी सबूतों के आगे नहीं चली।

जानकारों का कहना है कि सभी देश अपने पक्ष में और अपने हितों के अनुरूप लॉबिंग करते हैं। लेकिन तथ्य के आधार पर ही फैसला होता है। तथ्य यही हैं कि पाकिस्तान ने यूएन द्वारा घोषित आतंकियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। दूसरे आतंकवादी गतिविधियों के वित्तीय स्रोत को समाप्त करने के लिए भी गंभीर एक्शन नहीं लिए गए हैं। इसका खामियाजा उसे खुद भुगतना पड़ रहा है। अगर पाकिस्तान अभी भी कार्रवाई नहीं करता है तो अक्तूबर में होने वाली बैठक में भी उसकी उम्मीदें धूमिल ही रहेंगी।

अमेरिका और इजराइल संबंधों की नयी शुरुआत! रोम में मुलाकात करेंगे दोनों देशों के विदेश मंत्री

रोम। अमेरिका और इजराइल में सरकारें बदलने के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्री रविवार को रोम में मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और उनके इजराइली समकक्ष याइर लापिद के बीच दोनों देशों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के शासन के अंत के बाद इस मुलाकात को दोनों देशों के संबंधों की नयी शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है।

इस मुलाकात में इजराइल और हमास के बीच अनौपचारिक संघर्ष विराम को टिकाऊ बनाने और इजराइल की आयरन डोम मिसाइल प्रणाली को मजबूत बनाने पर चर्चा होने की उम्मीद है। ईरान के 2015 के परमाणु समझौते पर वियना में चल रही वार्ता इस बैठक का प्रमुख एजेंडा होगी। ट्रंप ने 2018 में इस समझौते से अमेरिका को बाहर निकालकर ईरान पर पाबंदियां लगा दी थीं, जिसका इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने समर्थन किया था। हालांकि, बाइडन ने इस समझौते को बरकरार रखने और विस्तार देने का वादा किया था।

ट्रंप ने प्रचार मुहिम के अंदाज में की रैली, राष्ट्रपति पद के चुनाव में गड़बड़ी का फिर लगाया आरोप

ओहायो (अमेरिका)। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से जाने के बाद पहली बार प्रचार मुहिम अंदाज में शनिवार को की गई अपनी रैली में राष्ट्रपति पद के चुनाव में गड़बड़ी के आरोप फिर से लगाए और डेमोक्रेटिक पार्टी के शासन में देश का भविष्य चिंताजनक होने की आशंका जताई। ट्रंप की इस रैली का मकसद उस रिपब्लिकन से बदला लेना था, जिसने उनके खिलाफ दूसरे महाभियोग की सुनवाई के पक्ष में मतदान किया था।

व्हाइट हाउस में ट्रंप के सहयोगी रहे मैक्स मिलर का समर्थन करने के लिए क्लीवलैंड के निकट ओहायो के लोरेन काउंटी फेयरग्राउंड में शनिवार को रैली आयोजित की गई। मिलर प्रतिनिधि सभा के सदस्य एवं रिपब्लिकन नेता एंथनी गोंजालेज को संसद की एक सीट के लिए चुनौती दे रहे हैं। गोंजालेज प्रतिनिधि सभा में पार्टी के उन 10 सदस्यों में शामिल हैं, जिन्होंने कैपिटल इमारत में छह जनवरी को हुए हमले के लिए भीड़ में कथित भूमिका को लेकर ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के समर्थन में मतदान किया था। ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के चुनाव का जिक्र करते हुए रैली में कहा, ''हमने बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा काम किया, जिसकी किसी को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अल्जीरियाई राष्ट्रपति ने नया मंत्रिमंडल गठित करने के लिए परामर्श शुरू किया

अल्जीयर्स। (एजेंसी)।

अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देलमदजीद तेब्बौने ने नए मंत्रिमंडल के गठन से पहले विचार-विमर्श शुरू कर दिया है। एपीएस समाचार एजेंसी ने कहा कि तेब्बौने ने शनिवार को यहां अपने कार्यालय में नेशनल लिबरेशन फ्रंट (एफएलएन) के महासचिव अबू अल-फदल बादजी की अगवानी की। समाचार एजेंसी के मुताबिक, बादजी ने पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। संसदीय मतपत्रों के परिणामों के आलोक में अल्जीरिया में राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करने के उद्देश्य से परामर्श किया जिससे नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो सके। प्रधानमंत्री अब्देलअजीज जेराड और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने 24 जून को संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार तेब्बौने को अपना इस्तीफा सौंपा है। तेब्बौने ने जेराड और उनकी टीम से नई सरकार बनने तक अपने पद पर बने रहने का अनुरोध किया। अनुच्छेद 113 में कहा गया है कि संवैधानिक न्यायालय द्वारा संसदीय चुनावों के अंतिम परिणामों की पुष्टि के बाद कैबिनेट इस्तीफा दे देता है। बुधवार देर रात संवैधानिक न्यायालय द्वारा 12 जून के संसदीय चुनावों के अंतिम परिणामों की घोषणा के बाद इस्तीफा दिया गया। संविधान अपने अनुच्छेद 103 में यह भी निर्धारित करता है कि सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है जब विधायी चुनावों के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति समर्थक बहुमत होता है और सरकार के प्रमुख द्वारा जब चुनाव विपक्षी दल के बहुमत में होता है। थ्र कॉन्स्टीट्यूशनल काउंसिल ने घोषणा की कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट (एफएलएन) ने संसद के निचले सदन में 407 सीटों में से 98 सीटों पर कब्जा कर लिया और स्वतंत्र सूची के उम्मीदवारों ने 84 सीटों पर कब्जा कर लिया, जबकि इस्लामिस्ट ओरिएंटेड मूवमेंट ऑफ सोसाइटी फॉर पीस (एमएसपी) ने 65 सीटें इक्ठ्ठी कीं। , इसके बाद 58 सीटों के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक रैली (आरएनडी) की पूर्व सत्ताधारी पार्टी है। परिणामों ने इस उत्तरी अफ्रीकी राष्ट्र में राजनीतिक परिदृश्य में एक उल्लेखनीय परिवर्तन किया है, क्योंकि यह पहली बार है कि 1989 में बहुदलीय प्रणाली की शुरूआत के बाद से स्वतंत्र उम्मीदवार संसद में दूसरी शक्ति बन गए हैं।

हाफिज सईद के घर के बाहर बम धमाके मामले में तीन और लोग हुए गिरफ्तार

लाहौर। (एजेंसी)।

पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के षड्यंत्रकर्ता और प्रतिबंधित जमात-उद-दावा (जेयूडी) के प्रमुख हाफिज सईद के घर के बाहर कार बम विस्फोट के लिए जिम्मेदार एक प्रमुख व्यक्ति की पहचान की है और मामले के सिलसिले में तीन और लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवाद निरोधी विभाग (सीटीडी) की तीन टीमों को कराची, पेशावर और शेखूपुरा में विस्फोट में शामिल लोगों के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए भेजा गया है। पंजाब प्रांत के कानून मंत्री बशारत रजा के अनुसार, बुधवार को हुए विस्फोट के सिलसिले में अब तक आठ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इस विस्फोट में तीन लोगों की मौत हो गई थी और 21 अन्य घायल हो गए थे।

सीटीडी के एक अधिकारी ने बताया, ''मुख्य संदिग्ध पीटर पॉल डेविड की सूचना पर लाहौर विस्फोट के सिलसिले में लाहौर, शेखूपुरा और पेशावर से तीन और संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है।'' उन्होंने बताया कि तीनों संदिग्ध डेविड के संपर्क में थे, जिसकी कार विस्फोट में इस्तेमाल की गई थी। उन्होंने बताया कि जांचकर्ता विस्फोट के 'षड्यंत्रकारियों' तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि विस्फोट के षड्यंत्रकर्ता की पहचान कर ली गई है और उसका नाम समीउल्लाह है, जो खैबर पख्तूनख्वा (केपीके) प्रांत का रहने वाला है। उन्होंने कहा, ''वर्तमान में समीउल्लाह दुबई में रह रहा है और उसके भाई ने कार में विस्फोटक रखा था।'' उन्होंने बताया कि पुलिस समीउल्लाह के भाई की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। उन्होंने कहा, ''कल हमारी टीम ने महमूदाबाद (कराची दक्षिण) में डेविड के आवास पर छापा मारा था और उसकी यात्रा तथा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए थे।''

डेविड को विस्फोट के एक दिन बाद बृहस्पतिवार को लाहौर हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। अधिकारी ने कहा कि डेविड के एमक्यूएम-लंदन से संबंध की भी जांच की जा रही है। मुहाजिर कौमी मूवमेंट (एमक्यूएम) पाकिस्तान में एक राजनीतिक दल है, जिसकी स्थापना 1984 में अल्ताफ हुसैन ने की थी। वर्तमान में, पार्टी दो मुख्य गुटों के बीच विभाजित है। एमक्यूएम-लंदन गुट का नियंत्रण हुसैन द्वारा किया जाता है, जो ब्रिटेन में स्व-निर्वासन में रह रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि डेविड के पास दोहरी नागरिकता है। अधिकारियों ने अभी तक पुष्टि नहीं की है कि उसकी अन्य राष्ट्रीयता बहरीन की है या संयुक्त अरब अमीरात की। अधिकारी के मुताबिक डेविड की पत्नी और एक बेटा पुलिस छापेमारी से पहले कराची स्थित अपने घर से निकल चुके थे। पंजाब पुलिस के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि डेविड ने अपनी वह कार उस संदिग्ध को मुहैया कराई थी, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सोसायटी जौहर टाउन में सईद के घर के बाहर पुलिस पिकेट पर खड़ी थी और रिमोट कंट्रोल के जरिए विस्फोट होने से 15 मिनट पहले वहां से निकल गई थी। कथित तौर पर कार में करीब 15 किलोग्राम विस्फोटक लगाया गया था। अज्ञात आतंकियों के खिलाफ धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। गौरतलब है कि 71 वर्षीय सईद आतंक वित्त पोषण मामलों में लाहौर की कड़ी सुरक्षा वाली कोट लखपत जेल में सजा काट रहा है।

चीन ने वुहान के लैब को नोबेल पुरस्कार देने की कही बात, ट्विटर यूजर्स ने निकाली भड़ास

नई दिल्ली। (एजेंसी)।

कोरोना वायरस ने अपना कहर पूरी दुनिया पर बरपाया है। कोई भी देश ऐसा नहीं बचा जहां कोरोना का यह घातक वायरस ना पहुंचा हो। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान के एक लैब से फैला है। अब ऐसे में चीन इसी लैब को सम्मानित करने की बात कर रहा है। चीन का कहना है कि वुहान के इस लैब को कोरोना वायरस की खोज के लिए नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाउ लिजियन ने कहा यह मानने के लिए लोगों की आलोचना की कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति वुहान में हुई थी क्योंकि यह पहली बार वहां पाया गया था और इस सिद्धांत को खारिज कर दिया कि यह प्रयोगशाला में बनाया गया था।

अब चीन के इस लैब को नोबल पुरस्कार देने की बात पर ट्विटर पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। जिसमें लोगों ने जमकर अपनी भड़ास निकाली है। एक ट्विटर यूजर ने लिखा चीन में वुहान लैब चीन के अनुसार चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार की हकदार है; तो ढ्ढस्ढ्ढ नोबेल शांति पुरस्कार का दिया जाना चाहिए। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा चीन वाले खुद नोबेल पुरस्कार लेने आएंगे या घर देने जाना पड़ेगा। एक दूसरे यूजर ने लिखा विश्व अर्थव्यवस्था को नष्ट करने लाखों लोगों को गरीबी में वापस लाने और लाखों लोगों की हत्या के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। एक और यूजर ने लिखा कि चलो मान लिया वुहान लैब को वायरस की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार मिले, आपको लगता है कि वे इससे लड़ने के लिए एक वैक्सीन विकसित करने के लिए बेहतर काम करेंगे। ट्विटर यूजर ने लिखा चीन तीसरा विश्व युद्ध शुरु करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए।

ओसामा को लेकर इमरान के मुंह से निकल गई थी दिल की बात, अब पाकिस्तान के मंत्री ने कहा- फिसल गई थी जुबान

इस्लामाबाद। (एजेंसी)।

आतंकवादियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान उस समय दुनिया के सामने बेनकाब हो गया था जब प्रधानमंत्री इमरान खान ने संसद में खड़े होकर अलकायदा के आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को शहीद बता दिया था। अब एफएटीएफ के फंदे से अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए छटपटा रहे पाकिस्तान ने कहा है कि वह ओसामा को आंतकवादी मानता है। इमरान खान के मंत्री ने कहा है कि पीएम की जुबान फिसल गई थी।

जियो टीवी को दिए एक इंटरव्यू में सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन को अलकायदा का आतंकवादी मानता है। उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद के खिलाफ जंग के समर्थन में मतदान किया था। हम यूएन के उस लिस्ट के वोटर हैं, जिसने ओसामा को आतंकवादी घोषित किया था।' चौधरी से जब इमरान खान की ओर से ओसामा को शहीद बताने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पीएम की जुबान फिसल गई थी।

पिछले साल जून में नेशनल असेंबली में भाषण देते हुए इमरान खान ने पाकिस्तान के एटबटाबाद में अमेरिका की ओर से किए गए ऑपरेशन को याद करते हुए कहा था कि ओसाम बिन लादेन शहीद हो गई थे। दिल की बात जुबान पर आई तो दुनिया के सामने पाकिस्तान को शर्मसार होना पड़ा और तब से ही इमरान के इस बयान से पीछा छुड़ाने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने टोलो न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि इस बयान को गलत संदर्भ से जोड़ दिया गया। उन्होंने इसके लिए मीडिया के एक हिस्से को दोषी बताया।

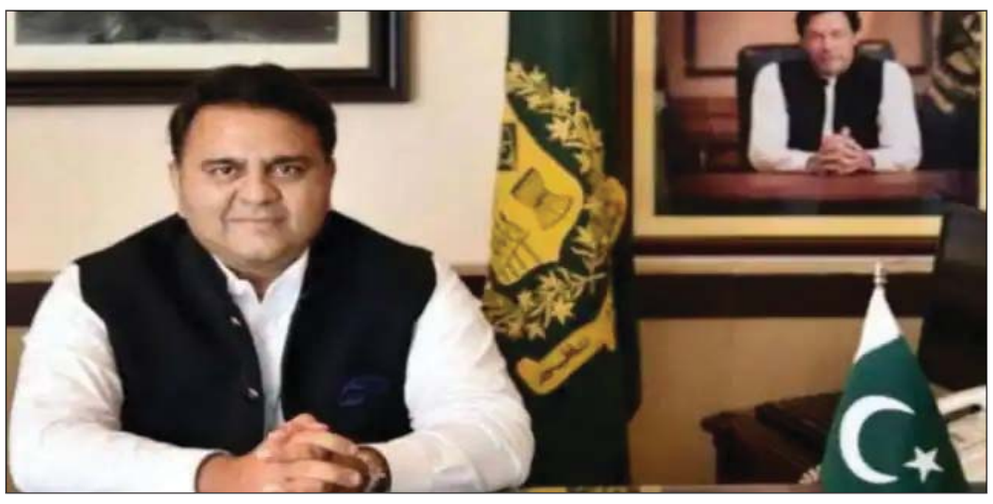

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

विख्यात उद्यमी महेश सवाणी आम आदमी पार्टी में शामिल, मनीष सिसोदिया ने किया स्वागत

क्रांति समय दैनिक

सूरत,दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में रविवार को सूरत के विख्यात उद्योगपति मनीष सवाणी आम आदमी पार्टी (आप) में शामिल हो गए। सिसोदिया ने सवाणी ने आप का पटका पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया। आप पार्टी में शामिल होने के बाद महेश सवाणी ने पत्रकार परिषद में कहा कि उन्होंने 51 वर्ष की आयु में राजनीति में प्रवेश किया है। गुजरात काम करने राजनीति में आया होने का उल्लेख करते हुए महेश सवाणी ने कहा कि कई लोगों ने उनसे कहा कि मुझे परेशान किया जाएगा। इसके बावजूद मैंने आप में शामिल होने का फैसला किया है। भले ही मुझे जेल जाना पड़े या गोली मार दी जाए। इसलिए मैंने नई जमीन पसंद की है। सवाणी ने कहा कि मुझे गरीब और मध्यम वर्ग की पीड़ा का अहसास है और समाज का काम करने के लिए राजनीति में आया हूं। कोविड सेंटरों को लेकर उन्होंने कहा कि इस पर राजनीति करना उचित नहीं है। कोरोनाकाल में लोगों का काफी आर्थिक नुकसन हुआ है। सवाणी ने कहा कि दिल्ली की सरकारी स्कूलें प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हो चुकी हैं। कोरोनाकाल में लोगों का बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है, लोग दर दर की ठोकरें खा रहे थे। पाटीदार समाज की बात करते हुए महेश सवाणी की आंखे छलक आईं। आम आदमी पार्टी में महेश सवाणी का स्वागत करते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह चुनाव के वक्ततय किया जाएगा। सूरत में आप के नगर पार्षद बेहतर काम कर रहे हैं। सिसोदिया ने दावा किया कि आनेवाले समय में कई लोग भाजपा छोड़कर आप में शामिल होंगे। भाजपा को झगड़ा पार्टी बताते हुए उन्होंने कहा कि वह सभी से लड़ाई करती रहती है। भाजपा शिक्षा के नाम पर लूट चलाना चाहती है। बता दें कि महेश सवाणी पाटीदार समाज से आते हैं और सूरत में विख्यात उद्योगपति है। भावनगर जिले के रापरडा गांव के मूल निवासी महेश सवाणी पीपी सवाणी ग्रुप के संचालक हैं। हीरा, शिक्षा और निर्माण व्यवसाय से जुड़े महेश सवाणी सामाजिक सेवा में भी अग्रसर हैं। वर्ष 2008 से महेश सवाणी पिता विहीन बेटियों की शादी करवाते हैं। ऊरी में शहीद हुए जवानों के बच्चों की भी उन्होंने मदद की है। महेश सवाणी के शामिल होने से आप को गुजरात में जमीन मिलने के साथ ही वित्तीय मदद और पटीदर समाज का साथ भी मिलेगा। सूरत समेत दक्षिण गुजरात में महेश सवाणी का वर्चस्व है। जिससे आम आदमी पार्टी को फायदा होने की संभावना है।

मनीष सिसोदिया की पत्रकार परिषद में आप की नगर पार्षद के पति ने किया आत्महत्या का प्रयास

क्रांति समय दैनिक

सूरत,रविवार को सूरत आए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पत्रकार परिषद में उस वक्त हंगामा हो गया, जब आम आदमी पार्टी (आप) की नगर पार्षद रत्ना दुधागरा के पति चिराग दुधागरा ने मिट्टी के तेल छिड़कर आत्म हत्या करने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत चिराग को पकड़ लिया। इस बारे में पुलिस ने फिलहाल कोई अधिकृत बयान नहीं दिया है। बता दें कि कुछ दिन पहले रत्ना दुधागरा ने आरोप लगाया था कि उसके पति चिराग ने भाजपा नेता से 25 लाख रुपए लिए हैं। जिसे लेकर दोनों के बीच झगडा हुआ और दोनों अलग हो गए। हांलाकि चिराग ने पत्नी रत्ना के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसका दांपत्यजीवन तोड़ने में आप के शहर के प्रमुख की बड़ी भूमिका है। चिराग ने कहा कि मेरा और रत्ना का डिवोर्स नहीं हुआ है। इसी मामले को लेकर चिराग दुगाधरा ने आज मनीष सिसोदिया की पत्रकार परिषद के बीच जीवन भारती कंपाउंट में अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़का और आग लगाने का प्रयास किया। हांलाकि मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया। चिराग दुधागर की पत्नी रत्ना दुधागरा सूरत वार्ड नंबर 3 से आम आदमी पार्टी की पार्षद है। रत्ना दुधागरा ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि भाजपा में शामिल होने के लिए 3 करोड़ रुपए की ऑफर की गई है।

लेकिन उन्होंने भाजपा विधायक की यह ऑफर ठुकरा दी थी। जिसके बाद उनके पति पर लालच देकर भाजपा में शामिल होने का दबाव डाला जा रहा था।

सायन पुलिस की चौकी में तोड़फोड़ करने वाले दो आरोपियों के सरघास पुलिस

क्रांति समय दैनिक

सूरत के सायन पुलिस चौकी पर दो उग्र लोगों पर हुई हिंसा, जनता के बीच दोनों हाथों से उठाकर बैठाया

सार-समाचार

प्राइवेट स्कूल संचालकों का फीस घटाने से इंकार, कोर्ट जाने की दी चेतावनी

राज्य में नया शैक्षिक सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन विद्यार्थियों को स्कूल नहीं बुलाया जाता। विद्यार्थियों को ऑनलाइन ही पढ़ाया जा रा है। ऐसे में विद्यार्थियों को फीस में राहत देने की मांग के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री भूपेन्द्रसिंह चूडास्मा ने कहा है कि सरकार चाहती है कि प्राइवेट स्कूलें पिछले साल की तरह इस वर्ष भी फीस में 25 प्रतिशत राहत दें। शिक्षा मंत्री के इस बयान का प्राइवेट स्कूलों के संचालकों का कड़ा विरोध दर्शाते हुए फीस में राहत देने से इंकार कर दिया है। इस संदर्भ में प्राइवेट स्कूल संचालकों की बैठक हुई, जिसमें फीस में किसी प्रकार की राहत नहीं देने का फैसला किया गया। स्कूल संचालकों का कहना है कि जारी वर्ष में फीस में राहत देने के शिक्षा मंत्री के बयान से हम सहमत नहीं हैं। पिछले साल 25 प्रतिशत फीस घटाने से स्कूलों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। 50 प्रतिशत अभिभावक फीस जमा करने में उदासीन रहे। स्कूल संचालकों ने कहा कि यदि इस वर्ष में राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर फीस घटाने को मजबूर करती है तो स्कूल संचालक कानूनी रास्ता अख्तियार कर राज्य सरकार के खिलाफ कोर्ट जाएंगे।

थलतेज से सोला तक का एलिवेटेड ब्रिज का उप मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण

उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने आज सरखेज-गांधीनगर हाईवे पर थलतेज से सोला के बीच बने एलिवेटेड ब्रिज का लोकार्पण किया। अहमदाबाद और गांधीनगर को जोड़ते सरखेज-गांधीनगर हाईवे पर लगातार बढ़ते परिवहन के कारण कई ब्रिजों का निर्माण किया जा चुका है। इसी कड़ी में अब थलतेज अंडरपास से गोता तक 42000 मीटर यानी 4.18 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड ब्रिज का निर्माण कार्य जारी है। जिसमें थलतेज अंडरपास से सोला ओवरब्रिज-रेलवे ब्रिज तक 1500 मीटर का छह मार्गीय फ्लाईओवर ब्रिज काम पूर्ण होने से आज इसका नितिन पटेल ने लोकार्पण किया। इस मौके पर नितिन पटेल ने कहा कि सरखेज-गांधीनगर हाईवे पर छह मार्गीय रास्ता खुलने से नागरिकों को आवाजाही सरल होगी और समय व ईंधन की बचत भी होगी। उन्होंने कहा कि थलतेज अंडरपास से गुजरने के बाद झायडस सर्कल तक काफी ट्रैफिक होने से वाहन चालकों को काफी मुश्किल होती थी। नागरिकों की सुखाकारी के लिए सड़क एवं आवास विभाग ने त्वरित फैसला कर थलतेज से गोता तक 6 मार्गीय एलिवेटेड कोरीडोर बनाने का कार्य शुरूकिया था,

क्रांति समय

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

जम्मू में संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, विस्फोटक सामग्री बरामद

जम्मू। जम्मू में एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से कुछ विस्फोटक सामग्री मिली है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संदिग्ध व्यक्ति बनिहाल का रहनेवाला है। उसे जम्मू के बाहरी इलाके में त्रिकूट नगर क्षेत्र से शनिवार रात गिरफ्तार किया गया। इस मामले में आगे विवरण की प्रतीक्षा है। अधिकारियों ने कहा कि संदिग्ध की गिरफ्तारी और विस्फोटक मिलने के बाद जम्मू संभाग में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

भारत में 50 हजार के पार हुए नए कोरोना मरीज, 1,258 लोगों की मौत

नयी दिल्ली। भारत में कोविड-19 के एक दिन में 50,040 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,02,33,183 हो गई और उपचाराधीन मामलों की संख्या गिरकर 5,86,403 रह गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार सुबह आठ बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार, इस संक्रामक रोग से एक दिन में 1,258 लोगों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 3,95,751 हो गयी। उपचाराधीन मरीजों की संख्या और कम होकर 5,86,403 हो गयी जो संक्रमण के कुल मामलों का 1.94 प्रतिशत है। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या लगातार 45वें दिन कोविड-19 के रोज आने वाले मरीजों की संख्या से अधिक है। इस बीमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 2,92,51,029 हो गयी है। मृत्यु दर 1.31 प्रतिशत है।

गैंगस्टरों और माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार की सख्त कार्रवाई, जब्त की 1,128 करोड़ की संपत्ति

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में अपराधियों, गैंगस्टरों और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखी है। एक साल और तीन महीने की अवधि में यूपी सरकार ने सख्त उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और एंटी-गैंगस्टर के तहत खूंखार गैंगस्टर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी सहित कम से कम 25 माफियाओं की 1128 करोड़ 23 लाख 97 हजार 800, 46 रुपये की चल-अचल संपत्ति सहित अवैध संपत्तियों को जब्त कर लिया है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त डीजीपी प्रशांत कुमार ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि इस अवधि के दौरान जिन संपत्तियों को जब्त और ध्वस्त किया गया है, उनमें से अधिकांश हाई-प्रोफाइल माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की हैं।

सरकार ने स्ष्ट को बताया- 31 जुलाई तक कोविड टीकों की 51.6 करोड़ खुराक उपलब्ध रहेंगी

नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने शनिवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि 31 जुलाई तक कोविड टीके की कुल 51.6 करोड़ खुराक उपलब्ध कराई जाएंगी जिनमें से 35.6 करोड़ खुराक पहले ही मुहैया करायी जा चुकी हैं। बच्चों के लिए टीका उपलब्ध कराने की स्थिति को लेकर केंद्र ने एक हलफनामे में कहा कि भारत के दवा नियामक ने 12 मई को भारत बायोटेक को उसके टीके कोवैक्सीन का क्लीनिकल ट्रायल दो से 18 साल के प्रतिभागियों पर करने की अनुमति प्रदान की थी और इस परीक्षण के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। अदालत को यह भी बताया गया कि डीएनए टीका विकसित कर रहे जायडस कैडिला ने 12 से 18 वर्ष के आयुसमूह पर क्लीनिकल ट्रायल पूरा कर लिया है और इसे वैधानिक मंजूरी मिलने के बाद यह टीका निकट भविष्य में 12 से 18 साल के बच्चों के लिए उपलब्ध हो सकता है। हलफनामे में सरकार ने यह भी कहा कि देश की पात्र आबादी का टीकाकरण करने के वास्ते टीका उपलब्ध रहेगा। वहीं, केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को यह भी बताया कि वे देश में कोविड-19 के मामलों में इजाफा होने की सूरत में इससे निपटने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और इसके बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत कर रहे हैं। शीर्ष अदालत में दायर हलफनामे में केंद्र ने कहा कि इस चरण में मामलों में फिर से वृद्धि होने की संभावना जुताना काल्पनिक होगा।

पीएम मोदी ने किया जेन गार्डन और कैजान अकादमी का उद्घाटन, भारत-जापान के रिश्ते होंगे मजबूत

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन (एएमए) में एक जापानी जेन गार्डन और काइज़न अकादमी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीए मोदी ने कहा कि, भारत और जापान जितना बाहरी प्रगति और उन्नति के लिए समर्पित रहे हैं, उतना ही आंतरिक शांति और प्रगति को भी हमने महत्व दिया है। जापानी ज़ेन गार्डन शांति की इसी खोज की, इसी सादगी की सुंदर अभिव्यक्ति है। अहमदाबाद में ज़ेन गार्डन और कैजान एकेडमी के उद्घाटन कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि, ज़ेन गार्डन और कैजान एकेडमी के लोकार्पण का ये अवसर भारत-जापान के संबंधों की सहजता और आधुनिकता का प्रतीक है। मुझे विश्वास है कि जापानी ज़ेन गार्डन, कैजान एकेडमी की स्थापना भारत-जापान के रिश्तों को और मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि, जापान की एक से बढ़कर एक कंपनियां आज गुजरात में काम कर रही हैं। मुझे बताया गया है कि इनकी संख्या 135 से भी ज्यादा है। ऑटोमोबिल से लेकर बैंकिंग तक, कंस्ट्रक्शन से लेकर फार्मा तक, हर सेक्टर की जापानी कंपनी ने गुजरात में अपना बेस बनाया हुआ है। पीएम ने वर्चुएल संबोधन में कहा कि,हमारे(भारत और जापान) पास सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों का मजबूत विश्वास भी है और भविष्य के लिए एक कॉमन विज़न भी! इसी आधार पर हम पिछले कई वर्षों से अपनी स्पेशल स्ट्रेटिजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप को लगातार मजबूत कर रहे हैं।

ऑक्सीजन विवादः गुलेरिया ने ऑडिट रिपोर्ट को बताया अंतरिम, केजरीवाल ने आपस में नहीं लड़ने की अपील की

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने दिल्ली की ऑक्सीजन आवश्यकता पर दी गई रिपोर्ट के बारे में शनिवार को कहा कि यह अंतरिम है और अंतिम शब्द नहीं है। वहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जोर देते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी वास्तविक थी। दिल्ली के अस्पतालों की ऑक्सीजन की जरूरत को कथित तौर पर बढ़ा-चढ़ा कर पेश करने को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे केजरीवाल ने इस विषय पर बेवजह की राजनीतिक बयानबाजी बंद करने और हर किसी से साथ मिल कर काम करने की अपील की, ताकि तीसरी लहर में किसी को भी दिक्कत नहीं हो। केजरीवाल ने ट्वीट किया, ''आपस में लड़ेंगे तो कोरोना वायरस जीत जाएगा।'' गौरतलब है कि एक दिन पहले आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच उस रिपोर्ट को लेकर जमकर जुबानी जंग हुई थी, जिसमें कहा गया कि कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में ऑक्सीजन की मांग चार गुना अधिक बतायी गयी। उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त पांच सदस्यीय समिति का नेतृत्व करने वाले गुलेरिया ने पीटीआई-से कहा, ''यह एक अंतिरम रिपोर्ट है। ऑक्सीजन की जरूरत में उतार-चढ़ाव होता रहा है और इसमें दिन ब दिन बदलाव होता है। यह विषय न्यायालय में विचाराधीन है। ''रिपोर्ट के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल सरकार पर ''आपराधिक लापरवाही'' बरतने का आरोप लगाया, तो वहीं उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि ''फर्जी रिपोर्ट'' भाजपा के कार्यालय में ''गढ़ी'' गई। केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, ''ऑक्सीजन पर आपका झगड़ा खत्म हो गया हो तो थोड़ा काम कर लें? आइए मिलकर ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि तीसरी लहर में किसी को ऑक्सीजन की कमी ना हो। दूसरी लहर में लोगों को ऑक्सीजन की भीषण कमी हुई। अब तीसरी लहर में ऐसा ना हो। आपस में लड़ेंगे तो कोरोना जीत जाएगा। मिलकर लड़ेंगे तो देश जीतेगा।'' सिसोदिया ने एक ट्वीट में भाजपा को ''भारतीय झगड़ा पार्टी'' बताते हुए कहा, '' भारतीय झगड़ा पार्टी के नेताओं को केवल झगड़ा करना आता है। इन्हें न ऑक्सीजन से मतलब है, न कोरोना की तीसरी लहर से। जब तीसरी लहर आएगी तब वे किसी और जगह चुनाव में झगड़े करा रहे होंगे। चुनाव खत्म होंगे तो फिर निर्वाचित सरकारों से झगड़ने में लग जाएँगे। '' उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित एक उप-समूह ने कहा कि दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की खपत ''बढ़ा-चढ़ाकर'' बतायी और 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का दावा किया, जो 289 मीट्रिक टन की आवश्यकता से चार गुना अधिक थी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक रणदीप गुलेरिया की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति ने कहा था कि दिल्ली सरकार ने ''गलत फॉर्मूले'' का इस्तेमाल करते हुए 30 अप्रैल को 700 मीट्रिक टन मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन के आवंटन के लिए दावा किया। वहीं, दो सदस्यों, दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (गृह) बी एस भल्ला और मैक्स हेल्थकेयर के क्लीनिकल डायरेक्टर संदीप बुद्धिराजा ने नतीजे पर सवाल उठाए। भल्ला ने अपनी आपत्ति दर्ज करायी और 30 मई को उनसे साझा की गयी 23 पन्ने की अंतरिम रिपोर्ट पर टिप्पणी की। रिपोर्ट में 31 मई को भल्ला द्वारा भेजे गए पत्र का एक अनुलग्नक है, जिसमें उन्होंने कहा कि मसौदा अंतरिम रिपोर्ट को पढ़ने से यह ''दुखद रूप से स्पष्ट'' होता है कि उप-समूह कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए छह मई के उच्चतम न्यायालय के आदेश की शर्तों का पालन नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि उप समूह ने जिस तरह कार्यवाही की इससे संकेत मिलता है कि कार्यवाही का उद्देश्य पहले से सुनियोजित और तय निष्कर्ष तक पहुंचना और दिल्ली को चिकित्सकीय ऑक्सीजन की कम मात्रा की सिफारिश करना था।

योगी सरकार ने 2017 के घोषणापत्र के वादों को पूरा करने का किया दावा

लखनऊ (एजेंसी)।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान जारी लोक कल्याण संकल्प पत्र में किसानों से किए गए कृषि विकास के वादे और किसानों से किए गए वादों को पूरा करने का दावा किया है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, योगी आदित्यनाथ सरकार की कृषि विकास और किसानों के उत्थान की यात्रा, 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपये के ऋण माफ करने के साथ शुरू हुई। इसके बाद प्रगतिशील और अभिनव किसानों को पहचानने के साथ-साथ उनकी उपज के लिए बीमा कवर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन किया गया। कृषि विकास की मजबूत नींव रखने से लेकर इसे लाभकारी क्षेत्र बनाने और किसानों की आय दोगुनी करने तक योगी सरकार के पास कई उपलब्धियां है। पिछले चार वर्षों में, राज्य सरकार ने 45.74 लाख गन्ना किसानों को 1,37,891 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड भुगतान किया है, जो कि बहुजन समाज पार्टी सरकार के दौरान किए गए भुगतान से दो गुना अधिक है और समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल से किए गए भुगतान से डेढ़ गुना अधिक है। योगी सरकार ने कृषि, किसानों और खेत मजदूरों के विकास के वादे को पूरा करते हुए न केवल रिकॉर्ड अनाज उत्पादन और खरीद हासिल की, बल्कि खरीद प्रक्रिया से बिचौलियों को खत्म करते हुए 72 घंटे के भीतर किसानों के खातों में सीधे भुगतान किया।

सूरत के हीरा कारोबारी महेश सवानी आप में शामिल

नई दिल्ली। सूरत के प्रसिद्ध हीरा कारोबारी महेश सवानी रविवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने टोपी और पटका पहना कर उनका पार्टी में स्वागत किया।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, महेश भाई, आम आदमी पार्टी में आपका स्वागत है। हम सब मिलकर गुजरात के विकास के लिए काम करेंगे। इस मौके पर मनीष सिसोदिया ने कहा, मुझे खुशी है कि गुजरात में पिछले 4 महीने में आम आदमी पार्टी का तेजी से प्रसार हुआ है। हमें जनता का स्नेह मिल रहा है। सूरत की जनता ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा कर सूरत की राजनीति में युवा और पढ़े-लिखे लोगों को चुनना शुरू कर दिया है। ये बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के लिए बेहद गर्व और सम्मान की बात है कि महेश सवानी, अरविंद केजरीवाल के विजन से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि महेश सवानी ने एक समाजसेवी के रूप में समाज के विकास के लिए काम किया है। अब गवर्नेंस में भी बदलाव लाना चाहते हैं। इनके अनुभवों से पार्टी और गुजरात की जनता को बहुत लाभ मिलेगा।

अपने जन्मस्थली पहुंचे राष्ट्रपति कोविंद ने कहा- सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे देश का सर्वोच्च पद मिलेगा

लखनऊ/ कानपुर देहात (एजेंसी)।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को कहा कि उन्होंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि वह देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होंगे। कोविंद ने कानपुर देहात जिले के परौंख गांव (अपनी जन्मस्थली) में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, ''मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने का सम्मान मिलेगा, लेकिन हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ने ऐसा कर दिखाया।'' राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं को भी श्रद्धांजलि दी और कहा, ''आज मैं जहां भी पहुंचा हूं, उसका श्रेय इस गांव की मिट्टी, इस क्षेत्र और आपके प्यार एवं आशीर्वाद को जाता है। बुजुर्गों को माता-पिता की तरह सम्मान देना हमारे संस्कार हैं और मुझे खुशी है कि हमारे परिवार में बड़ों को सम्मान देने की यह परंपरा अब भी जारी है।''

कोविंद ने कहा, मैं कहीं भी रहूं, मेरे गांव की मिट्टी की खुशबू और मेरे गांव के लोगों की यादें हमेशा मेरे दिल में बसी रहेंगी। परौंख गांव मेरी मातृभूमि है, जहां से मुझे देश सेवा करने की प्रेरणा मिलती रही है। राष्ट्रपति ने कहा, '' मातृभूमि से मिली इस प्रेरणा ने मुझे उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय से राज्य सभा, राज्य सभा से राजभवन और राजभवन से राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाया है।'' राष्ट्रपति कोविंद रविवार सुबह परौंख गांव में अपने जन्म स्थान पहुंचे जहां उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख?यमंत्री योगी आदित?यनाथ ने उनका स्वागत किया। पुलिस अधीक्षक के जन संपर्क अधिकारी विकास राय ने बताया कि पटेल और आदित्यनाथ ने कोविंद का उनके पैतृक गांव परौंख में स्वागत किया। कोविंद अपनी पत्नी और बेटी के साथ पथरी देवी मंदिर गए, जहां उन्होंने पूजा-अर्चना की। उन्होंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल औरमुख्यमंत्री के साथ परौंख गांव का दौरा किया। कोविंद परौंख गांव के प्राथमिक स्कूल पहुंचे, जहां उन्हें लोगों को संबोधित किया। कोविंद अपने पुराने परिचितों, विधायकों और भाजपा पदाधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वह पुखरायां जाएंगे, जहां वह 60 से अधिक लोगों से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति 28 और 29 जून को लखनऊ रहेंगे। राष्ट्रपति के कार्यक्रम के मुताबिक, वह सोमवार को कानपुर से पूर्वाह्न 10 बजकर 20 मिनट पर विशेष ट्रेन से लखनऊ के लिए रवाना होंगे और वह पूर्वाह्न 11 बजकर 50 मिनट पर लखनऊ रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। रेलवे स्टेशन से वह सीधे राजभवन आएंगे, जहां वह दोपहर का भोजन करेंगे। राज भवन में ही शाम छह बजे एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य गणमान्य लोग शामिल होंगे। कोविंद सोमवार रात को राजभवन में विश्राम करेंगे। वह मंगलवार को पूर्वाह्न साढ़े 11 बजे लोकभवन से भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आंबेडकर मेमोरियल एवं सांस्कृतिक सेंटर की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद, वह शाम साढ़े छह बजे लखनऊ हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।

तीन दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सुरक्षा तैयारियों की करेंगे समीक्षा

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने तीन दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंचे। इस दौरान वह लेह में पूर्व सैनिकों से मिले और उन्होंने कहा कि, हमारी सेना के जवानों, पूर्व सैनिकों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में कितना सम्मान है ये बताने की जरूरत नहीं है। 30-40 वर्षों से वन रैंक, वन पेंशन की समस्या चली आ रही थी। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही वन रैंक, वन पेंशन की मांग को पूरा किया है। बता दें कि राजनाथ सिंह लेह में सैन्य अभियानों की तैयारियों का जायजा लेंगे।मई से चल रही चीन और भारत के बीच के तनाव को दूर करने के लिए दोनों देशों के राजनायिकों के बीच वार्ता हुई है। बता दें कि रक्षा मंत्री सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा निर्मित ढांचागत परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।

जगन ने बेरोजगार युवाओं की पीठ में छुरा घोंपा: टीडीपी

अमरावती (एजेंसी)।

विपक्षी तेलुगू देशम पार्टी ने रविवार को आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को अपने लगातार झूठे वादों और नवीनतम जॉब कैलेंडर जैसे फर्जी दावों के साथ उनकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं।

टीडीपी सांसद के. राममोहन नायडू ने मुख्यमंत्री से हाल ही में जारी नौकरी कैलेंडर को तुरंत वापस लेने की मांग की और इसे रोजगार रहित कैलेंडर कहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपनी पदयात्रा के दौरान युवाओं से किए गए नौकरी के वादों को पूरा करने के लिए एक नया और वास्तविक कैलेंडर जारी करना चाहिए। सांसद ने कहा कि 26,000 शिक्षक पदों को भरने के लिए डीएससी अधिसूचना जारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को राज्य में 2.30 लाख नौकरियों के रिक्त पदों को भरने के लिए चुनाव से पहले किए गए अपने भव्य वादे को पूरा करना चाहिए। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, राममोहन नायडू ने कहा कि जगन रेड्डी के बेरोजगार युवाओं से किए गए झूठे वादों के कारण वाईएसआरसीपी को 2019 में 175 में से 151 विधायक मिले थे। सीएम बनने के बाद जगन रेड्डी ने युवाओं की आकांक्षाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। सीएम ने चुनाव से पहले 2.30 लाख सरकारी रिक्तियों के बारे में बात की थी लेकिन अब उनके जॉब कैलेंडर में सिर्फ 10,000 रिक्तियों का संकेत दिया गया है। राममोहन नायडू ने दावा किया कि सीएम की रोजगार विरोधी नीतियों के कारण राज्य में बेरोजगारी दर साल 2018-19 के 3.6 प्रतिशत से बढ़कर अब 13.5 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने कहा कि जगन को केवल वादे तोड़ने के लिए जाना जाता है। उन्होंने याद किया कि चुनाव के दौरान जगन ने कहा था कि वह लड़ेंगे और केंद्र से आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिलाएंगे। अब, मुख्यमंत्री ने केवल यह कहकर एक और वादा तोड़ दिया कि केंद्र में भाजपा सरकार को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद से कुछ भी नहीं किया जा सकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से लोगों को यह समझाने की मांग की कि उनकी पार्टी के सांसद राष्ट्रीय स्तर पर विशेष दर्जे के लिए लड़ने के लिए इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जगन रेड्डी विशेष उड़ानों पर भारी मात्रा में खर्च करके दिल्ली का गुप्त दौरा कर रहे हैं।

मायावती ने किया बड़ा ऐलान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी बसपा

लखनऊ। (एजेंसी)।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के साथ गठबंधन से इनकार करते हुए रविवार को दावा किया कि दोनों राज्यों में अगले वर्ष के प्रारंभ में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। बसपा प्रमुख ने रविवार को ट्वीट के जरिये अपनी प्राथमिकता जाहिर की। उन्होंने ट्वीट किया, ''मीडिया के एक न्यूज चैनल में कल से यह खबर प्रसारित की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा आम चुनाव ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और बीएसपी मिलकर लड़ेगी। यह खबर पूर्णतः गलत, भ्रामक व तथ्यहीन है। इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है तथा बसपा इसका जोरदार खंडन करती है।''

मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा, ''वैसे इस सम्बन्ध में पार्टी द्वारा फिर से यह स्पष्ट किया जाता है कि पंजाब को छोड़कर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले वर्ष के प्रारंभ में होने वाले विधानसभा चुनाव बसपा किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबन्धन करके नहीं लड़ेगी अर्थात् अकेले ही लड़ेगी।'' उन्होंने कहा, ''बसपा के बारे में इस किस्म की मनगढ़न्त व भ्रमित करने वाली खबरों को खास ध्यान में रखकर ही अब बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चन्द्र मिश्र को पार्टी की मीडिया सेल का राष्ट्रीय संयोजक बना दिया गया है। साथ ही मीडिया से भी यह अपील है कि वह बहुजन समाज पार्टी और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदि के सम्बन्ध में इस किस्म की भ्रमित करने वाली अन्य कोई भी गलत खबर लिखने, दिखाने व छापने से पहले एससी मिश्र से उस सम्बंध में सही जानकारी जरूर प्राप्त कर लें।''

उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष बिहार के विधानसभा चुनाव में बसपा ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और एआईएमआईएम के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था जिसमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) भी शामिल हुई थी। अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा के बैनर तले सुभासपा और एआईएमआईएम ने गठबंधन किया है और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दलों को एकजुट करने की मुहिम चला रहा रहे हैं। सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने अभी हाल में यह दावा किया था कि वह भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं।

पुडुचेरी में सत्ता हथियाने के लिए पिछले दरवाजे से घुसने की कोशिश कर रही भाजपा

पुडुचेरी (एजेंसी)।

पुडुचेरी मंत्रिमंडल के मंत्री रविवार को शपथ लेंगे, जिसमें भाजपा के दो मंत्री और अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस (एआईएनआरसी) के तीन मंत्री , मुख्यमंत्री एन. रंगासामी के 7 मई को पदभार ग्रहण करने के 51 दिन बाद कैबिनेट में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था और पार्टी ने छह सीटें जीतीं। यह पहली बार था जब भगवा पार्टी ने केंद्रशासित प्रदेश में अपना खाता खोला। बीजेपी एआईएनआरसी के नेतृत्व वाली सरकार में जूनियर पार्टनर के तौर पर सत्ता साझा कर रही है। रंगासामी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के बाद, वह कोरोना संक्रमित हुए और उन्हें चेन्नई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब मुख्यमंत्री अस्पताल में थे, भाजपा ने अपने तीन नेताओं को विधायक के रूप में नामित किया और इस प्रकार 33 सदस्यीय सदन में पार्टी की संख्या नौ हो गई। 2021 के चुनावों में, रिकॉर्ड छह निर्दलीय जीते, और इसमें से तीन विधायकों ने भाजपा को अपना समर्थन दिया। इसने कई सिद्धांतों को जन्म दिया कि भाजपा अधिक मंत्री पद पाने के लिए एआईएनआरसी के साथ सौदेबाजी के खेल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। उसकी कोशिश है कि यदि संभव हो तो वह मंत्रिमंडल में ऊपरी स्थान हासिल करें। रंगासामी, जो चेन्नई के अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, उन्होंने इस दौरान चुप्पी साधे रखी और पुडुचेरी के भाजपा नेतृत्व और यहां तक कि केंद्रशासित प्रदेश के पार्टी प्रभारी राजीव चंद्रशेखा के साथ बातचीत करना बंद कर दिया। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को रंगासामी के साथ भाजपा के राज्य नेतृत्व के साथ-साथ चंद्रशेखर के साथ बातचीच शुरू करवाने के लिए काफी अनुनय-विनय करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने अनिच्छा से सहमति व्यक्त की और इससे राज्य भाजपा और रंगासामी के बीच की खाई बढ़ गई। इस बीच, तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री और द्रमुक के वरिष्ठ नेता एस दुरईमुरुगन ने खुले तौर पर कहा कि भाजपा पिछले दरवाजे से सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। के जीवनानंदन, राजनीतिक पर्यवेक्षक और माहे विकास मंच के निदेशक ने कहा, देश भर में भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड पुडुचेरी में हम जैसा देख रहे हैं वैसा ही है। इसने कांग्रेस पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं जैसे ए नामसिवयम और जॉन कुमार को अपने साथ कर लिया। इसी तरह, कई वरिष्ठ स्थानीय नेता भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने कहा, हालांकि भाजपा अभी भी देश के इस हिस्से में एक गैर-इकाई है और वे पिछले दरवाजे से प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। रंगासामी को अपने क्षेत्र की ठीक से रक्षा करनी होगी अन्यथा भाजपा बहुमत हासिल करने के लिए काम करेगी और पिछले दरवाजे से मुख्यमंत्री का पद पाने का प्रयास करेगी। रविवार को रंगासामी मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ, राजनीतिक और सामाजिक हलकों में मिलियन-डॉलर का सवाल यह है कि क्या भाजपा गठबंधन को परेशान करेगी और ऊपरी हाथ हासिल करने की कोशिश करेगी या क्या वह जूनियर पार्टनर के रूप में संतुष्ट होगी। देश भर में भाजपा द्वारा अपनाई गई राजनीतिक लाइन इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भगवा पार्टी प्रयोग के खिलाफ नहीं है और वह मुख्यमंत्री पद पाने के लिए कोशिश कर सकती है।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशक : सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास , (भाटेना) हो.सो अंजना सुरत
गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक :सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/751000 (Subject to Surat jurisdiction)